पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

www.samaymaya.com

पंजीयन क्रमांक RNINDPM\HIN\20345/12/1/2006/TC

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

cell : 9300755803-9425125569
Phone Fax : 91-731-2530859
Websites : www.samaymaya.com
www.geocities.com/samaymaya/jan09.pdf
www.geocities.com/corruption2india/corruptindia.html
www.geocities.com/corruption2india/corruptMP.html
E-mail : mwc@indiatimes.com
: linkdage@hotmail.com,
: linkadage@indiatimes.com

(c) all copyrights reserved with chief editor,do not publish any matter without prior permission.

वर्ष 1 अंक 49 | इंदौर, सोमवार 12 जनवरी से 18 जनवरी 2009 तक | पृष्ठ 8 मूल्य रु. 2/-

2 ✦एक पाप छुपाने, सौ पाप और

3 ✦भ्रष्ट जालसाजों का अड्डा म.प्र. सूचना आयोग

4 ✦शिवराज मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विभाग

5 ✦डॉ. पंडित का पांडित्य है भ्रष्टाचार में

6 ✦म.प्र. म.बा. विकास में करोड़ों का भ्रष्टाचार

7 ✦पी जाते हैं अरबों का पानी

गड़रिये से अमेरिकी राष्ट्रपति, इतिहास का पहला अश्वेत

इतिहास बदलो, विश्व का भविष्य, बनाओ खुशहाल

बहुराष्ट्रीय कं. हथियार निर्माताओं की कठपुतली न बनो

अमेरिका में ढ़ाई शताब्दी के इतिहास में पहली बार श्वेतों के लिए अश्वेतों द्वारा बनाए गए श्वेत भरन में अश्वेत बैठ कर श्वेतों पर राज्य करेगा। न केवल अमेरिका की वरन् पूरे विश्व की राजनीति में बदलाव होगा। ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि भावी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने शैशव काल में बकरियां भी चराई थीं। इसलिए उसने गरीबी देखी व भोगी है। अमेरिका की अधिकांश आबादी संकर प्रजाति की है। मूल अमेरिकी जो रेड इंडियन कहलाते हैं। वो भारतीय आदिवासियों की तरह ही जीवन यापन करते और रहते हैं।

अमेरिकी भावी राष्ट्रपति भी मुस्लिम पिता जो अफ्रीकी मूल का था ने ईसाई कैथोलिक गौरी महिला से शादी की थी जिससे ओबामा का जन्म हुआ था, अर्थात् यह भी संकर प्रजाति का ही है। **शेष पेज 2 पर**

विश्व के सबसे बड़ा आतंकवादी बुश के राष्ट्रपतित्व का अंत

श्वेत राक्षस 21वीं शताब्दी की प्रथम दशाब्दिका खलनायक

करोड़ों की हत्या, करोड़ों घायल, अमेरिका की भी बर्बादी का जिम्मेदार

21वीं शताब्दी की प्रथम दशाब्दि का विश्व का सबसे बड़ा खलनायक बन गया अमेरिकी राष्ट्रपति बुश। जिसका कार्यकाल 19 जनवरी 2009 को समाप्त हो जाएगा।

इस श्वेत राक्षस बुश अपनी लालची प्रवृत्ति के चलते जहां एक तरफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हजारों एशियाई को मरवाया वहीं दूसरी ओर उसकी आड़ में अफगानिस्तान पर आक्रमण कर लाखों अफगानी नागरिकों को मार ओसामा की आड़ में दक्षिणी एशिया में अपने परम शत्रु रूस, चीन, के साथ ही अपनी कठपुतली देशों पर निगरानी रखने, वहां फैलाने, तेल का खेल करने, ईराक और ईरान पर आक्रमण करने की नीयत से वहां कब्जा कर लिया।

इसके बाद ईराक पर परमाणु और रासायनिक हथियारों की आड़ में तेल पर कब्जा करने के लिए आक्रमण कर लाखों की हत्या की और करोड़ों को घायल किया। पूरा ईराक नेस्तनाबूद करके हर जगह छान मारा, परंतु कहीं कोई परमाणु या रासायनिक हथियार न मिला। जबकि दुनिया को ये दिखाया जातारहा पर वहां तेल के कुओं पर कब्जा कर अपना खेल किया, पिछले 5वर्षों में इसने ईराक और अफगानिस्तान पर हैवानियत का वो तांडव किया। बूढ़ी औरतों, बच्चियों के साथ खुले में नाटो सेनाओं ने लाखों के साथ बलात्कार किया, वहां इन नाटों सैनिकों से उत्पन्न औलादें स्कूल जाने लायक हो चुकी हैं। दुनिया को मानवाधिकार पढ़ाने वाले ने स्वयं मानवता को कितना तार-तार **शेष पेज 2 पर**

मंदी उपभोक्ता वस्तुओं पर नहीं

केंद्र की जालसाजी

गेहूं का निर्यात-खाद्य वस्तुओं का वायदा व्यापार

भारत में खाद्य एवं उपभोक्ता वस्तुओं पर मंदी का कोई असर नहीं पढ़ा है, बेशक पिछले तीन माह से कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की आंशिक कीमतों में स्थिरता आई है।

बड़ी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जिसमें हिन्दुस्तान लीवर, आई.पी.सी, रिलायंस, गोदरेज आदि ने अपने उच्चस्तरीय व्यापार, जिसमें पूंजीगत विनियोजन होता है कि मंदी की भरपाई को उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखकर उनकी मात्रा का वजन में कमी कर दी है। केंद्र सरकार के वित्त विभाग वाणिज्य व कृषि मंत्रालयों ने नई चाल खेलते हुए एक तरफ गेहूं के निर्यात को खुली छूट दे दी है, वहीं खाद्य वस्तुओं, अनाज दलहनों और तिलहनों के वायदा व्यापार को खुली छूट दे दी है, इससे नेशनल कामोडिटी स्टॉक एक्सचेंजों में ऐसी कृषि उत्पादित वस्तुओं के खुल के सट्टेबाजी होने से रुपए 15-14 रुपए किलो की शक्कर रुपए 20/- तक जा पहुंची है, वहीं गुड़ जैसी वस्तुओं के भाव बढ़कर रुपए 24 से रुपए 28-30 प्रति किलो जा पहुंचा है। वहीं नहाने , कपड़े धोने के साबुनों, डिटर्जेंट पाउडरों की कीमतों में भी 25 से 30% की वृद्धि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कर दी है।

वही हाल खाद्य तेलों का है, मंदी का रोना रोने वालों से पूछो कि आम आदमी को तो दो वक्त की रोटी फिर भी उसी भाव में पड़ रही है। यदि खाद्यान्नों, दालों, तेलों में मंदी का असर होता तो कीमतें आसानी से 25 से 40% तक गिर जानी चाहिए थी इसके विपरीत 5 से 10% की जो मंदी की लहर उपभोक्ता वस्तुओं में बताई जा रही उन सब वस्तुओं के फुटकर बाजार में उपभोक्ताओं का उसका लाभ तीसरे महीने में भी नहीं मिला है। जो पूरी तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां, थोक विक्रेताओं के खाते में ही जा रहा है। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय से कहकर जो गृह ऋण, कार ऋण की ब्याज दरें कम की हैं, वो उच्च मध्यमवर्गीय व मध्यमवर्गीय को आकर्षित कर सकता है, पर आम उपभोक्ता **शेष पेज 5 पर**

क्या अमेरिका मंदी दूर करने भारत-पाक को लड़वाएगा

लोकसभा चुनाव जीतने, युद्ध की ओर

आतंकवाद सत्ता चलाने का हथियार, कांग्रेस कितनी ईमानदार

मुंबई बम कांड 26.11 तब हुआ जब 5 विधानसभाओं के चुनाव सिर पर थे, जब-जब कांग्रेस चारों तरफ से भ्रष्टाचार जालसाजियों और नाकामियों से घिर जाती है तब वह आतंकवादी घटनाएं करवाकर जनता और मीडिया का ध्यान परिवर्तन कर देती है। य़ह उसका पिछले 35वर्षों से आजमाया हुआ सटीक हथियार बन चुका है। यह बिलकुल फिल्मी स्टाइल है कि चलती हुई जनता की जिंदगी की कहानी में मारधाड़, हिंसा, रक्तपात न हो तो फिल्म में मजा नहीं आता।

अब जबकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं तो सत्ता में बैठे खलनायकों को अपनी नायक की छवि प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है कुछ मारधाड़, ठांय-ठायं कुछ जहाजों के घन-घनाने, बम बरसाने, कुछ पानी के जहाजों से स्टंट सीनक रते हुए हवाई जहाजों की उड़ाने फिर बम बरसाने, आगजनी, कुछ चीखें, कुछ धुंआ उठता हुआ टीवी चैनलों को दिखाने का मौका मिला तो इपने विज्ञापन के स्लॉट अच्छी कीमतों पर बेच सकें। देश की जनताहर पल टीवी से चिपकी रह कर भारतीय रणबांकुरों का रण कौशल देखे, फिर अमेरिका जैसा गुंडा बंदर भारत और पाकिस्तान दोनों को सीख भी देता चले और माल भी बेचता रहे। हमारे सत्ताधीश 10-20 हजार सैनिकों को मारकर और मरवा कर बहादुरों की श्रेणी में आकर अपने कुकर्मों से ध्यान बंटाकर चुनाव जीत सकें।

अभी हाल ही की सितम्बर-अक्टूबर की ही तो बात है जब कांग्रेस मुसलमानों के वोटों के चक्कर में खुले में बोल रही थी सिमी एक अच्छा संगठन है। अमरसिंग और मुल्ला मुलायम सिंग बोल रहे थे सिमी पर से प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए, हिन्दु संतों को सेना के अधिकारियों को आंतकवादी बताकर उन्हें जेल भिजवाया गया, वहां उन्हें भयानक प्रताड़ना देकर मनचाहे तरीके से बयान लिए गए और पूरे प्रदेश में कर्नल पुरोहित के बहाने पूरी सेना को बदनाम किया गया था। जब न्यायालयों में पेशी की बारी आई और साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने सच उगलना शुरू किया तो तत्काल ही बम्बई बम कांड करवाकर तिहरी चाल चली गई। एक तरफ राज्यों के चुनावों में जनता को दहशत बांट कर दिल्ली, राजस्थान और मिजोरम जीत गया तो दूसरी तरफ संतों, सेना के अफसरों की सच्चाई से ध्यान बंटाने का षड्यंत्र रचा गया, ताकि जनता और मीडिया उनके कुकर्मों पर ध्यान न दे सके। तीसरा अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यानाकर्षण किया जा सके।

यदि सचमुच ही सारा कारनामा पाकिस्तानी आतंकवादियों का है तो ये हरामखोर महाराष्ट्र की कांग्रेसी सरकार, एसटीएफ, एटीएस, मुम्बई पुलिस उन्हें सारा डाटा क्यों नहीं देना चाहती, क्योंकि इनके कुकर्मों क पोल खुल जाएगी और कांग्रेसी कुकर्मों पर चढ़ा चोला नग्न हो जाएगा, जहां उनकी घिनौनी हरकतों और पीछे बैठे नेताओं की सच्चाई अंतरराष्ट्रीय मंच पर सामने आ जाएगी, कांग्रेस और इसके वर्तमान सहयोगी दल सपा व अन्य मुस्लिम वोटों को पाने और सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिरने को तैयार रहते आए हैं।

शेष पेज 3 पर

सारी जांच एजेंसियां भ्रष्टों से करती हैं, महीना वसूली

लोकायुक्त, आ.अ.व्यू.सी.बी.आई. सब तनखैय्या

भोपाल। म.प्र. में बैठी राज्य सरकार की दोनों एजेंसियां लोकायुक्त और आर्थिक अन्वेषण ब्यूरों ने पिछले वर्ष भर में कितने नए प्रकरण बनाए, कितनों के आरोप पत्र न्यायालयों में प्रस्तुत किए, कितनों को सजा हुई। तो इन सारे हरामखोरों ने पूरे प्रदेश में एक सैकड़ा भी नए प्रकरणों, आरोप पत्र न्यायालयों में प्रस्तुति, सजा के नाम पर सैकड़ा तो बहुत दूर 25 अर्थात एक चौथाई को भी सजा नहीं दिलवा पाये, जबकि राज्य शासन के एक सैकड़ा से ज्यादा विभागों, 500 के आसपास भ्रष्ट इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों, 1000 से ज्यादा राज्य प्रशासनिक अधिकारियों, 5000 से ज्यादा इंजीनियरों, 5000 से ज्यादा डॉक्टरों, 20000 से ज्यादा टीचर्स, 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों में कोई भी इन हरामखोरों को भ्रष्ट नहीं मिला और हम जहां भी जाते हैं दुःख है कि ईमानदारों के दर्शन को तरस जाते हैं।

लोकायुक्त, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय जांच एजेंसी, अनुसंधान विश्लेषण शाखा (रिसर्च एनालिसस विंग) आदि सभी में हैं तो वहीं सारे खाकी वर्दी के जालसाज, भ्रष्ट शासकीय डकैतों का गिरोह जो थानों में बैठकर, **शेष पेज 2 पर**

साप्ताहिक
समय माया

संपादकीय

एक पाप छुपाने, सौ पाप और

शास्त्रों ने, ऋषियों, मुनियों, संत-महात्मा, शताब्दियों से मानवों को सच बोलने की शिक्षा दे रहे हैं, पर मानव जो सत्ता में बैठे होते हैं। अपनी हर बात, तथ्यों, कृत्यों जो अपनी सत्ता चलाने में, अपने हित साधने में प्रयोग करते हैं। वो यदि गलत भी हैं, तो भी उन्हें सच सिद्ध करने के लिए वह 100 गलत काम और कर देंगे, एक गलत को सही ठहराने के लिए वैसे ही जैसे कि अधिकांश झूठे व्यक्ति एक झूठ को सच सिद्ध करने के लिए 100 झूठ बोलते हैं।

हमारे राष्ट्र में केंद्र शासन में सत्ता चला रही कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भी वही कर कर रहे हैं। पिछले 60 वर्षों से वो अपने हित साधन में पहले एक अपराध करते हैं। फिर उसी अपराध को सही ठहराने के लिए सौ पाप और करते है, इसका स्पष्टीकरण पाठक स्वयं जानते हैं।

कांग्रेस और वर्तमान आतंक का चोली दामन का साथ रहा है। जब वह यूपी की सत्ता में रहती थी और भ्रष्टाचारों के आरोपों से घिर जाती थी तो अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, फैजाबाद में हिंदू-मुस्लिम के किसी न किसी बहाने से दंगे करवाकर जनता और मीडिया का ध्यान बंटाकर सैकड़ों को मरवा डालती थी, अब जब से कांग्रेस यूपी से बाहर हुई है। वहां अलीगढ़ जैसे इलाकों में न तो दंगे हो रहे है न हर चार छह महीनों में कर्फ्यू लग रहे है। उसका सत्ता चलाने में आतंकवाद एक बड़ा सटीक हथियार है।

वही हाल अब केंद्र में कर रही है, जब-जब भ्रष्टाचार के आरोपों घिर जाती है। देश में दो-चार दस आतंकी घटनाएं करवा देती है जनता और मीडिया का ध्यान परिवर्तित हो जाता है वह इन आतंकवादी घटनाओं की जांच में क्षेत्रीय पुलिस, जनता को उलझाकर मीडिया को मसाला देकर खुद नए भ्रष्टाचार करने में जुट जाती है।

कांग्रेस का ये चरित्र आजादी के बाद से रहा है कि वो एक पाप को छुपाने को सौ पाप करती है। वर्तमान में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध इसी आतंकवाद के दम पर करने के लिए तैयार बैठी है ताकि इस तरह वह जनता का ध्यान बंटाकर चुनाव जीत ले, उसने अपने पिछले 5 वर्षों के शासनकाल में न केवल ढेरों पाप किये, जिसमें परमाणु समझौते के बहाने राष्ट्र की सुरक्षा को ही गिरवीकर दिया, इस मुद्दे पर जब संसद गिरने की बारी आई तो नोट कांड करवा दिया, जब उस कुकृत्य में फंस गई, तो बंगलुरू, अहमदाबाद, जयपुर में आतंकवादियों की आड़ में बमकांड करवा दिये।

धूर्तों की परिभाषा में इसका आधारभूत है कि वो एक पाप करते हैं। उसको पुण्य सिद्ध करने के लिए वो सौ पाप और करते हैं। यही हाल हमारे देश की सत्ता चलाने वाले असली सत्ताधीश आईएएस अर्थात इंडियन एब्यूसिंग सर्विस आफिसर्स का भी है ये हरामखोर, धूर्त कौम है, जो अपने आपको सुपरमैन समझती है। नियम कानूनों को जेब में रखकर चलती है। हरवक्त अपने पाप को छुपाने को सौ पाप करती है और करने को तैयार रहती है। चाहे वो सत्ता को चलाने और अपने हित साधन में कुछ भी हो, भले ही सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने वाली बात को भी धमकी मानकर उसमें भी समन्स नोटिस, वारंट जारी करवाने से भी नहीं चूकती, जबकि उन जिलाधीशों के जिसके अंतर्गत उन्हें सारी जानकारी धारा 4 (1) अ और ब में कम्प्यूटर्स डालना थी। 12/10/05 से 3 वर्ष गुजर जाने के बाद भी अभी तक इंटरनेट साइटों पर नहीं डाली गई।

बुरहानपुर जिलाधीश से जब ये जानकारी मांगी गई तो बंदा अपनी श्रेष्ठता दिखाते हुए श्री अजमेरा के साथ धमकी वाले अंदाज में पत्रोत्तर देकर आवेदन ही निरस्त कर दिया। जिस जनता के धन से ये कानूनों का पालन करने के लिए बैठाये जाते हैं। सत्ताधीश उन कानूनों का स्वयं कैसा मजाक उड़ाते है। फिर वही एक पाप को पुण्य बनाने के लिए 100 पाप करते जाते हैं।

लोकायुक्त ...

पेज 1 से जारी

सब ही जांच एजेंसियों में भ्रष्ट पुलिसिये जिनका धर्म है वसूली

चोरों, जेबकतरों से लेकर वैश्यावृत्ति करने वाली औरतों, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, नौकरी दिलाने के नाम पर अड्डों पर भेजने वाली औरतों, लड़कियों, महिला छात्रावासों के नाम पर चलने वाले कोठों, जुए-सट्टे के फंड चलाने वालों, पर्ची काटने वालों, चोरी का नाम बेचने वाले कबाड़ियों, नशे की पुड़िया बेचने वाली औरतों, दलालों से लेकर फरारी काटने वालों, वारंटियो से महीना वसूली कर छुट्टा छोड़ने वालों से महीना, हफ्ता वसूलने वाले, अवैध शराब, जालसाजों के अड्डों, कार्यालयों, सड़क पर ठेला लगाने वालों से वसूली कर जीवन चलाने वालों, चोरी, डकैती, बलात्कार, जेबकटी, चैन छपटने वालों आदि से वसूली कर अपराधियों को भगाने, अपराधियों से चाय-नाश्ता, दारूखोरी करने वालों का ये गिरोह अगर लोकायुक्त, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई कहीं भी चला जाए, आदतन अपराधी कैसे सुधर सकते हैं। स्वाभाविक है जहां भी जाकर बैठेंगे चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो या राज्य पुलिस के सहायक, उप निरीक्षक हो, दाड़ में हरामखोरी, भ्रष्टाचार का खून कैसे छूट सकता है। यह प्रकृति बदस्तूर लोकायुक्त, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई में जाकर बढ़तीही है, घटती नहीं, फिर और भी आसानी से बिना वर्दी के नागरिकों की भेषभूषा में ज्यादा बड़े और लंबे अपराध करते हैं। अधिकांश विभागों के भ्रष्टों को समय माया जैसे साप्ताहिक पत्रों के खोजी पत्रकारों के सहारे उन के अधिकारियों को घेरकर दबाव बनाकर महीना वसूली शुरू कर देते हैं।

यदि कोई भी नागरिक, पत्रकार, कर्मचारी, विभागीय अधिकारियों की ठोस साक्ष्यों के आधार पर शिकायत करता है तो उन हरामखोरों, भ्रष्टों पर लोकायुक्त कार्यालय से कार्यवाही हो न हो, परंतु महीना वसूली अवश्य शुरू हो जाती है। ऐसे 50-100 नहीं हजारों प्रकरण हैं जिनमें भ्रष्ट अधिकारियों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, मंत्रीयों आदि की शिकायत नागरिकों, पत्रकारों, विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गई, उस पर सीधी कार्यवाही करने, जांच करने न्यायालयों में प्रकरण प्रस्तुत किए नहीं, किए परंतु आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो, लोकायुक्त, सीबीआई, में पदस्थ बाबुओं से लेकर कांस्टेबलों, सहायक उप या निरीक्षक से लेकर वहां बैठे उप अधीक्षक, अधीक्षकों ने वसूली अवश्य शुरू कर दी आखिर लोकायुक्त बने मुख्यालय में बैठे रिपुदमन दयाल सेवानिवृत्ति के बाद भी इतने सालों से कैसे ज़मा बैठे हैं, फिर वर्षभर की उनका प्रगति सूचना देखी जाए तो अंगुलियों पर गिन लीजिए। पूरे प्रदेश की जांच करने, आरोप पत्र प्रस्तुत करने से लेकर सजा दिलवाने तक की समीक्षा जबकि हमारे पास अपुष्ट सूत्रों के अनुसार परिवहन विभाग भर से ही रुपए 25 लाख से ज्यादा हर महीने पहुंचता है, फिर वाणिज्य कर, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, लोकस्वास्थ्य, जल संसाधन, महिला, बाल विकास, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, आबकारी, नगरीय विकास, नगरनिगमों, पालिकाओं परिषद्रों, विद्युत मंडल, प्रदूषण मंडल, महिला आदिवासी कल्याण आदि से कुल मिलाकर रुपए 2 करोड़ प्रतिमाह की बंदी पहुंच जाती है। तो फिर कैसे ये नमक हरामी कर उन भ्रष्टों, जालसाजों को पकड़ें? आखिर इंदौर में बैठे लोकायुक्त एस.पी. बिन कैसे वर्षों से एक ही स्थान पर कुंडली मारे बैठे हैं।

म.प्र. वाणिज्यकर में बैठे उपायुक्त आर.सी. पालीवाल की शिकायतें मकानों के फोटों समय माया ने अपने 2005-06 के अंकों में चिपका दिए थे। लोकायुक्त भोपाल से भले ही प्रत्यक्ष कार्यवाही न भी हुई, बाद में उपायुक्त पालीवाल ने श्री अजमेरा व अन्य पत्रकारों को गाली बकते हुए वाणिज्य कर के कर्मचारियों ने सुना जिसमें उसने कहा था कि इन पत्रकारों के कारण मेरा सारा वेतन हर महीने लोकायुक्त की चंदी में चला जाता है। लोकायुक्त के ही लोगों ने सन 2005 में सहा. आयुक्त राजीव जैन की रुपए 25 लाख वसूलने के चक्कर में हत्या कर दी थी। अब उसकी पत्नी वाणिज्य कर में नौकरी कर रही है।

लोकायुक्त आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में हजार व्यक्तियों से ज्यादा का स्टॉफ पूरे प्रदेशभर में है, जिस में आई.जी. स्तर के अधिकारियों से लेकर हर संभाग में एस.पी. स्तर के अधिकारी बैठे हैं। टी.आई., उपनिरीक्षक, सहा. निरीक्षकों से लेकर कांस्टेबल स्तर के इन अधिकारियों, कर्मचारियों को वेतन भतों से लेकर मकान की सुविधाओं तक पर हर माह रुपए 30 करोड़ से ज्यादा का व्यय पूरे प्रदेश में किया जाता है, पर परिणामों में वर्षभर में 50 प्रकरण भी नहीं बना पाते ये हरामखोर जबकि शिकायतें मय दस्तावेजों के हर महीने बढ़ती ही जा रही हैं। कौन सा विभाग है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, परंतु इन्हें बिलकुल नहीं दिखता।

इंदौर पुलिस के ही उपनिरीक्षक आर.के. गुर्जर है जिसके भाई के नाम से पाटनीपुरा चौराहे पर दुकान है। 54 नम्बर में विद्या विजय स्कूल है। करोड़ों की सम्पत्ति होने के बाद भी उस बंदे की सम्पत्तियां किसी को नहीं दिख रही। ऐसे ही आरटीओ में तिवारी एक निरीक्षक है जो खुलकर वाहनों से वजन ज्यादा है या अन्य कारणों में फंसा कर किसी भी राजमार्ग पर खड़े होकर वसूली कर रहा है। इसकेपास भी विजयनगर अरण्य में करोड़ों का लाइफ केयर हॉस्पिटल है। करोड़ों की अन्य सम्पत्तियां हैं। इसे भी लोकायुक्त ने आज तक हाथ नहीं लगाया है। ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं पूरे प्रदेश में जिसमें पुलिसकर्मियों ने करोड़ों की सम्पत्ति इकट्ठी की है, पर लोकायुक्त के नोटों के नयन सुखों की कुछ नहीं दिखता। फिर ये सब पुलिस से आए हुए होते हैं। इसलिए अपने जाति भाइयों को नहीं छेड़ते।

वही हाल केंद्रीय जांच ब्यूरो का है, वहां भी सभी राज्यों की पुलिस से ही प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। इसलिए अपनी खूनी दाड़ को लगे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के चस्के को पूरा करने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों, पेट्रोल कंपनियों, गैस डीलरों व सभी केंद्र सरकार के विभागों जिसमें आयकर, कस्टम व एक्साइज से महीना वसूली कर अजगरों की तरह चुपचाप केंद्र से आए प्रकरणों में उलझे रहते हैं। दिखाकर भ्रष्ट आयकर अधिकारियों, कस्टम एंड एक्साइज से लेकर वित्त एवं बीमा कंपनियों के भ्रष्टाचारियों से वसूली चलती रहती है।

फिर प्रकरणों के मामलों में भी आखिर सीबीआई, लोकायुक्त, आ.अ.अ. ब्यूरो सब ही न्यायालयों में आरोप पत्रों को इतना कमजोर बनाते हैं कि अपराधी और भ्रष्ट आसानी से बच निकलते हैं। इसका मूल कारण है कि जांच के समय ही इतना लेनदेन हो जाता है कि स्वयं अपराधियों को बचाते रहते हैं।

कांग्रेस-भाजपा

पेज 1 से जारी

कांग्रेसी हेमराज कलपोनी ने तो एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की जो इनकी हिटलिस्ट में नहीं था। छोटे मियां भाजपा के आलीराजपुर के विधायक नागर सिंह चौहान पर डकैती और हत्या के प्रयास के दमगे जुड़े हैं। सीहोर के रमेश सक्सेना पर प्रापर्टी में धोखाधड़ी के अलावा दूसरी धोखाधड़ियों के मामले चल रहे हैं। देवरी के भानु राणा भी पाक दामन नहीं है, उन पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज हैं।

कांग्रेसी पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध समाप्त किस गस प्रकरणों की सूची

केस नं.	मंत्री	समाप्ति दिनांक
सीआर नं.24/04	दिग्विजयसिंह	9/5/08
एलए. 42/99-00	जमुनादेवी	7/12/06
एलए 1/99	प्यारेलाल केनवार	30/06/06
एलए 2/97-98	सत्यदेव कटारे	03/02/05
ईआर 171/02	सुभाष सोजतिया	17/09/03
ईआर 292/01	सुभाष सोजतिया	21/12/06
एलए 55/00(1)	सुभाष सोजतिया	17/05/04
एलए 20/97-98	हरवंशसिंह	25/06/08
ईआर 262/01	सज्जनसिंह वर्मा	19/01/04
ईआर 362/02	महेंद्र बोध	27/07/04
ईआर 142/03	उर्मिला सिंग	23/08/04
एलए 10/02	गंगाबाई उरते	20/04/05
एलए 28/99	राजेंद्रकुमार सिंग	26/04/08
ईआर 277/02	राजा पटैरिया	12/12/03

इन भ्रष्टों से जितनी वसूली होनी थी कर ली गई, दो बार से सरकार नहीं तो क्या वसूली होगी, इसलिए ये हरामखोर लोकायुक्त ने ही प्रकरण बंद कर नाटक का पटाक्षेप कर दिया।

पूर्व और वर्तमान के विरुद्ध लंबित प्रकरणों की सूची

ईआर 19/08	शिवराजसिंह चौहान और अजय विश्नोई	29/4/08
ईआर 398/07	कैलाश विजयवर्गीय	10/4/07
ईआर 27/07	,,	20/6/07
ईआर 20/08	जयंत मलैय्या	2/05/08
ईआर 67/07	बाबूलाल गौर व लक्ष्मीकांत शर्मा	30/06/07
ईआर 103/07	अजय विश्नोई व जयंत मलैय्या	23/07/07
ईआर 413/07	जयंत मलैय्या	19/03/07
ईआर 12/07	हिम्मत कोठारी	14/05/07
ईआर 139/05	लक्ष्मीकांत शर्मा	25/07/05
ईआर 449/07	जयंत मलैय्या	31/03/08
ईआर 02/07	अनोप मिश्रा	03/04/07
ईआर 53/05	मोती कश्यप	04/06/05
ईआर 174/08	अखंड प्रतापसिंग	19/08/08
ईआर 247/07	चौ. चंद्रभान सिंग	25/01/08
ईआर 1550/07	कमल पटेल	26/09/07

वर्तमान और पूर्वमंत्री लोकायुक्त के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गियों के विरुद्ध प्रकरण उनकी सरकार रहने तक वसूली के काम आएंगे।

श्वेत राक्षस..

पेज 1 से जारी

बिखेरा जाकर वहां की बूढ़ी औरतों से लेकर 10-12 वर्ष की लड़कियों से लेकर जवान औरतों से पूछिये।यह हर काल, हर युग में हर आक्रमणकर्ता, आक्रांता करता है, इन्होंने उसकी हर सीमा पार की है। ऐसा नहीं कि ये नाटो फौजों ने केवल औरतों के साथ किया, बल्कि ये सब खेल छोटी उम्र के पुरुषों के साथ भी किया गया। जिसकी चित्रावली सन 2005-06 में समय माया में छापी जा चुकी है।

फिर जिसके मस्तिष्क में लालची और राक्षसी प्रवृत्ति भरी हो उसके लिए क्या देश, क्या विदेश। दूसरी तरफ इसके ईराक पर अनावश्यक आक्रमण के चक्कर में इंग्लैंड के टोनी ब्लैयर को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने मित्र राष्ट्रों की सेना के सैकड़ों सैनिकों को भी अपनी हवस पूरी करने के लिए न केवल मरवा दिया वरन वहां के सत्ताधीशों को भी अपने ही देश में जनता और सैनिकों के परिवार का कोपभाजन भी बनना पड़ा।

तीसरी तरफ अपने ही देश में अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के चलते एक-एक कर सैकड़ों बैंकों को दीवालियेपन का मुहं देखना पड़ा, बेशक उसमें भी धूर्तता यह की गई कि जितना पैसा, धन पूरी दुनिया के भ्रष्टों ने लेकर जाकर अमेरिका की बैंकों में जमा किया था, उन सबकी देनदारियों से वहां के सारे बैंक दीवालिया हो जाने के कारण पूरा डूब गया। अब सारे राष्ट्रों के सत्ताधीश, नेता, मंत्री से लेकर भ्रष्ट अधिकारियों, उद्योगपतियों आदि व अन्य का जो पैसा वहां डूब गया और ये व्हाइट हाऊस का आठ वर्षों का ये व्हाइट डेबिल बुश ने इस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, जब ज्यादा हल्ला मचने लगा उसी के देश में तो उसने 700 अरब डालर के पैकेज की घोषणा करके अपना पिंड छुड़ा लिया। इसके विपरीत बैंकों के दीवालियेपन की न तो जांच की कोई बात उठी, न विदेशी जमा धन के बारे में कहीं कोई सुगबुगाहट हुई।

वैसे इस व्हाइट डेबिल बुश की ये चाल भी सफल ही रही और अमेरिकी बैंक विदेशी धन को न केवल डकारने में सफल रहे, वरन् मंदी की आड़ में विदेशियों की नौकरियों से निकाल कर विदेशियों को सानी से उके देश लौटाने में भी सफल रहे। जबकि इसके विपरीत अमेरिकी डालर के रेट अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ गए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को 150 डालर पहुंचा कर अमेरिकी तेल कंपनियों और सटोरियों ने न केवल अपनी जेबें भरी, वरन उसका पुनः 5 वर्ष पुरानी अवस्था में ला पटकने से विदेशी तेल कंपनियों को भी उत्पादन घटाने पर मजबूर कर दिया। जाते-जाते डेबिड ने अपनी हर चाल को कामयाबी से खेला, ठीक है कि ईराक में उसने पत्रकार का जूता भी झेला, जो उसकी आंतरिक सच्चाई को प्रगट कर गया।

बहुराष्ट्रीय ..

पेज 1 से जारी

वर्तमान तक 259 वर्षों के इतिहास में गौरो लोगों को ही यहां राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला जो एक इसके पूर्व अश्वेत ने राष्ट्रपति बनने का सपना देखा था वह था मार्टिन लूथर किंग, जिसकी इन श्वेतों ने सपना पूरा होने से पूर्व ही हत्या कर दी थी, अर्थात श्वेतों की निगाह में अश्वेत अभी भी हेय हैं। जिसका सीधा प्रमाण है कि श्वेतों ने इस अश्वेत ओबामा को भी काफी धमकियां दी और चुनाव के दौरान हत्या का भी प्रयास किया था।

वर्तमान अमेरिका और दुनिया का परिदृष्य सामने है जहां अमेरिका और विश्व में अमेरिकी जालसाजियां और यूरोपीय समुदाय की विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से विश्व के राष्ट्रों के भ्रष्ट सत्ताधीशों को पर्याप्त विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक के माध्यम से धन बांटकर कर्ज में डुबोकर अपनी शर्तें मनवाकर पूरी दुनिया के विकासशील और अविकसित राष्ट्रों की जो योजना बनाकर शोषण की चाल चली थी के परिणाम स्वरूप न केवल स्वयं ही मंदी की चपेट में आ गया, वरन् यूरोप के अनेकों देशों, जिसमें उसका खास पिछलग्गू ब्रिटेन की भी अनेकों बैंकों को डुबो दिया।

बुश के शासनकाल में अमेरिका की जो बर्बादी हुई है बराक को न केवल उस बर्बादी को रोकना है वरन मंदी की चपेट से उत्पन्न हुई बेरोजगारी, उद्योग धंधों के बंद होने या भारी घाटे से उबारना है। पिछले अर्द्धदशक से अमेरिका ने दुनिया पर अपनी दादागिरी थोंपने , अपने हथियारों का बाजार बनाए रखने के लिए अपने अन्य उत्पादों को बेचने, एशियाई बाजारों पर कब्जा बनाए रखने, अपना महत्व स्थापित करने के लिए आतंकवाद को खुला संरक्षण दिया। तेल के खेल में ईराक पर कब्जा किया, दक्षिण एशिया में कब्जा बनाए रखने के लिए ओसामा की आड़ में अफगानिस्तान पर कब्जा कर वहां से पाकिस्तान, ईराक, चीन, भारत में अपनी कारगुजारियां करता रहा है। वास्तविकता में अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा गुंडा और आतंकवादी की छवि बना चुका है। विश्व में नया अश्वेत राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा इस छ वि को कैसे निकारता है यह भविष्य बताएगा।

20 जनवरी 09 से बराक अमेरिकी के नए राष्ट्रपति पद पर आसीन हो जाएंगे, बेशक सामने आंतरिक और बाहरी दोनों चुनौतियां हैं। कैसे ये अश्वेत राष्ट्रपति उन चुनौतियों को सुलझा कर एक नए न केवल अमेरिका, वरन् विश्व में युद्ध, आतंक विहीन समृद्ध विश्व की नींव रखेगा, यह भविष्य के गर्भ में है।

निःसंदेह ज्यादा बड़े फेरबदल की उम्मीदें लगाना हो तो बेमानी होगा, फिर भी आधारभूत सोच चूंकि वंशानुगत होती है, फिर बचपन से इस उम्र में इस मुकाम तक पहुंचने में जिस वातावरण से होकर जिंदगी गुजरी होती है, उसका असर भी सहज स्वाभाविक होती है, जो कि हर व्यक्ति की कार्यशैली का हिस्सा होती है, भविष्य में कार्य की पद्धति वही होती है। परिवर्तन तो होगा, हो सकता है, वह तत्काल दृष्टिगोचर न भी हो, परंतु अमेरिका का भविष्य वही निश्चित करेगी।

सूचना आयोग में भी चुन-चुनकर रखे हैं, जालसाज

भ्रष्ट जालसाजों का अड्डा म.प्र. सूचना आयोग

6-6 महीने तक नहीं भेजे जाते निर्णय

भोपाल। सूचना का अधिकार अधि. 05 के लागू होते समय जनता में आशा की किरण जागी थी कि शायद अब शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो सकेगा, पर धरती पर मानव में 99% ईमानदार तो हैं। जिन्हें मौका नहीं मिला, बाकी जिसे मौका मिले और वो नियत बिगाड़ने से चूक जाएं। धन की माया के लपेटे में आने से चूक जाएँ ऐसा संभव नहीं।

सूचना के अधिकार अधि. 05 की अंतिम कड़ी और या ये कहें कि शीर्ष पर बैठा सूचना आयोग भी जब ऐतिहासिक भ्रष्ट मुखेरे श्वानों का गिरोह हो, तो इनसे न्याय और कानून की मंशा के अनुरूप कार्य की उम्मीद ही बेमानी हो जाती है। मु.सू.आ. पी.पी. तिवारी का जीवन म.प्र. शासन के विधि सचिव के रूप में पहले मंत्रालय में सत्ताधीशों और पूंजीपतियों के हित साधने और इस आड़ में धन डकार कर कार्य करते-करते गुजरा, फिर वहां से उस मुखेरे को अपनी चरणदासी की सेवा के बदले मुख्य सूचना आयुक्त बना कर, इसीलिए उपकृत किया गया कि वो इनकी चरणदासी करते हुए इनकी कठपुतली बन नृत्य करें, तो इस मुखेरे ने अनावेदकों का तबीयत से धन डकार कर सबको राहत देता रहा, वहीं हाल दोनों धूर्त आयुक्त, जिनका पुराना भ्रष्टाचारी का इतिहास रहा है, धूर्त इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अधिकारी इकबाल अहमद, एक सेवानिवृत्त दिनेश जुगरान इंडियन क्राइम प्रोटेक्शन सर्वि का अधिकारी रहा, तो इनसे कैसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है। इन हरामखोरों की चालों में, एक से एक नए शिगूफे किया करते हैं। निर्णय देने के बाद भी 6-6 माह तक निर्णय की प्रतियां ही उपलब्ध नहीं करवाई जाती। कार्यालय में जावक दिखा जी जाती है। पर आवेदक और अपीलार्थी को उसीक प्रतियां प्राप्त नहीं होती।

यहां बैठे जालसाजों की जालसाजी का आलम ये है कि इन्हें हाथ से भी कोई आवेदन और अपील दो तो भी ये निठल्ले हरामखोरों की फौज एक से डेढ़ महीने बाद आवक दिखाती है। फिर किसी भी पत्र के पंजीयन में ये अनावेदकों का नाम और आवेदन की तारीख तक नहीं डालते ताकि इन श्वानों के कुकर्मों पर आंच न आए।

सूचना का अधिकार अधि. 05 भले ही केंद्र सरकार ने बनाया हो, परन्तु राज्य सरकार के भ्रष्ट मुखेरे मुख्य सचिव, विधि सचिव, स्वयं भ्रष्टाचार का रोना-रोने वाला मुख्यमंत्री शिवराज ने सबने उसकी व्याख्या अपने-अपने तरीके से कर ली है। मार्च 08 में म.प्र. शासन ने संसोधन कर उसमें जवाब देने की अवधि 160 दिन कर डाली। जैसे जनता के धन से चलाई जाने वाली सरकार इनके बापों की जागीर हो, ये कुछ भी करें कैसे भी, कितना भी डकारे, कोई इनसे कुछ न पूछे, फिर 24 नवंबर 08 की कैबिनेट मीटिंग में एक तुगलकी निर्णय और लिया गया कि बिना राज्य सरकार से पूछे किसी को कोई जानकारी नहीं दी जायेगी, मु.मं. शिव अपने धूर्त, भ्रष्ट सलाहकारगणों के इशारे पर नाचकर उन हरामखोरों को बचाकर स्वयं अपने लिये परेशानी खड़ी करते और करवाते है। अर्थात इन दो आदेशों से भ्रष्टों की मानसिकता का स्तर और जालसाजियों का पता स्वमेव चल जाता है। किस प्रकार इन जालसाजों ने इस अधिनियम का पूर्ण रूप से गला घोंटने की कोशिश की है।

म.प्र. सरकार में 2003 के अंत से भाजपा सरकार आई उसने संभागीय स्तर के नियंत्रण अधिकारियों को जिनके नियंत्रण में पूरे जिलों में प्रगति और कार्यों की समीक्षा का कार्य है। यदि उनको सूचना के अधिक में पत्र दिया जाता है तो चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, महिला बाल विकास, जनसंपर्क, संभागीय आयुक्त, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा आदि अधिकांश विभाग यह पत्र देकर कि आप हर जिला कार्यालय में सीधे आवेदन दें। जिला कार्यालय के अधिकारियों, जिलाधीश कार्यालय धन वसूली के समय, भ्रष्टाचार के धन में हिस्सा बंटाने के लिए तो संभागीय कार्यालय है। पर हरामखोर सूचना के अधिकार में जानकारी देने के नाम पर धारा 6 (3) के अंतर्गत भी आवेदन कानून के अंतर्गत भेजने से भी मना कर देते हैं। ऐसे अनेक मामलों में बज प्रथम व द्वितीय अपील दी गई तो भी मुख्य सूचना आयुक्त में बैठे इन मक्कार भ्रष्टों ने भी अपीलें स्वीकार करके निरस्त कर दी।

अब यक्ष प्रश्न यह है कि आखिर संभागीय स्तर के अधिकारियों जो कि नियंत्रण और देखरेख के लिए बैठाए गए हैं। इन पर भी जनता का शासन के माध्यम से करोड़ों रुपए वेतन, भत्तों व अन्य कार्यों में खर्च करना, समीक्षा, जिलास्तर के अधिकारियों की प्रगति, सतर्कता और नियंत्रण करना ही है, तो सूचना के अधिकार में जानकारियों को आवेदक को उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। आखिर इंदौर संभाग के सूचना आयुक्त इकबाल अहमद कैसे ऐसे अपीलों को धड़ाधड़ निरस्तकर संभागीय स्तर के अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे कम से कम 20 निर्णय हमारे कार्यालय में है।

अभी तक सूचना आयोग में हजारों अपीलें भेजी गई जिसे भ्रष्ट हरामखोरों को दंड दिया गया, जबकि आवेदकों को अधि. के अनुसार क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होने के उपरांत भी आयोग के निकंमें आवेदकों को ही परेशान करने की मानसिकता लेकर किसी भी आवेदक को परेशान करने से बिल्कुल नहीं चूकता, जबकि आवेदक से लेकर अपील के समय भोपाल आने-जाने के खर्चों को अपीलार्थी को भुगतने पड़ते हैं।

जबकि केंद्रीय आयोग अपीलार्थी को उसके खर्चे के भुगतान के लिए भी अनावेदक/प्रति अपीलार्थी से भुगतान के आदेश देता है। इस राज्य सूचना आयोग को भ्रष्ट आसानी से लेन-देन कर अपीलों को शब्दों के मायाजाल में उलझाकर निरस्त करवा लेते है। जिनके बारे में पूर्व में छाप चुके हैं।

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण

रुपए 178 करोड़ के ठेके में समय विस्तार व महंगाई का लाभ

सनावद। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता इंदिरा सागर बांध की नहरों के निर्माण के कार्य हेतु यह कार्यालय पिछले 30वर्षों से ज्यादा समय से कार्यरत है। जहां पूर्व मुख्य अभियंता रघुवंशी के सेवानिवृत्ति के साथ ही पहले से चल रहा भ्रष्टाचार न केवल कई गुना ज्यादा हो गया, वरन कार्य और निर्माण की प्रगति उससे दुगुनी गति से मंद या कहिये बंद सी हो गई।

दोनों ही बड़े और महाभ्रष्ट ठेकेदार कर्णसिंग और बी.सी. बिहानी द्वारा इंदिरा सागर, नहरों में अधिकांश कार्य न केवल इनके पास ही हैं, क्योंकि इन हरामखोर जालसाजों द्वारा सुपरवाइजर से लेकर मुख्य अभियंता अध्यक्ष से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक को ये धूर्तों का गिरोह जेब में रखकर चलता है। इन जालसाजों ने अधिकांश ठेकों को हथिया तो लिया पर एक तरफ भी काम पूरा न होने के कारण अधिकांश पर एक तरफ भी काम पूरा न होने के कारण अधिकांश भुगतान अटक गए तो दूसरी तरफ बैंकों से लिया गया ऋण, नगद साख भी चुक गई तो कार्यशील पूंजी के अभाव में दोनों ही जालसाजों के यहां के इंजीनियरों और कर्मचारियों को महीनों से पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो कार्य क्या खाक करेंगे?

दूसरी तरफ ओंकारेश्वर की बायीं तट नहर का वृहत स्तर का रुपए 178 करोड़ का जो ठेका सोम के साझेदार करणसिंग ने ठेका लिया था वह भी अब रुपए 204 करोड़ का हो गया। साथ ही अक्टूबर 06 में यह ठेका 2वर्ष में पूरी नहर निर्माण 5 वर्ष की गारंटी के साथ दिया गया था।

इसके विपरीत नवम्बर 08 गुजर

ओंकारेश्वर नहर चहुंओर भ्रष्टों का तांडव

जाने के बाद भी ओंकारेश्वर नहरों का निर्माण 40% अधूरा है। बेशक इसके पीछे कुछ कर्णसिंग की मजबूरियां थी तो कुछ अधिकांश जालसाजियां। सोम के इस साझेदार कर्णसिंग ने एक तो न.घा. भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त हुए इंजीनियरों जिसमें आर.पी. सक्सेना व अन्य कइयों को अपने ही यहां नौकरियों पर रख लिया, दूसरा काम भी गुणवत्ता की तो छोड़ औपचारिकता का भी पूर्ण जानबूझकर इसलिए नहीं करवाया गया ताकि समय विस्तार लेकर यह दो वर्ष का कार्य 4 वर्ष में भी पूरा करने की नियत नहीं है। क्योंकि अनुबंध के 5वर्ष का समय जिसमें रख रखाव का कार्य भी ठेकेदार को ही करना था। पूरा करने और अधिकांश बिल का पैसा हजम करने की नियत है। यदि समय विस्तार दिया गया तो महंगाई का भुगतान भी करना पड़ेगा, अब जबकि अनुबंध में निर्माण कार्य पूर्ण करने का समय पूरा हो चुका है। कार्य पूरा नहीं हुआ है। अब जबकि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मुख्यमंत्री के पास है, सबसे पहले ठेका निरस्त किया जाना चाहिए, सुरक्षा निधि जब्त कर जहां के जहां कर्णसिंग के स्वयं के ठेके चल रहे हैं तत्काल सारे बिलों का भुगतान रोक ओंकारेश्वर बायीं तट नहर के नुकसान का आंकलन कर सोम और कर्णसिंग पर दंड ठोका जाना चाहिए, साथ ही जो गुणवत्ताहीन कार्य किया गया है। अधिकांश बिलिंग जो की गई है, वह सैद्धांतिक गुणवत्तायुक्त कार्य की की गई है, परंतु जहां खुदाई में मिट्टी, मुरम या हल्की चट्टानों की खुदाई गई है। यदि कठोर चट्टानें निकली थीं तो उनके चट्टे कहां बना कर मंडारित की गई है। यह बताया जाए?

जहां नहरों की भराई को परा, पीली मिट्टी से 1'-1' की परत बिछाकर मशीनों से पानी डालकर दबाई जाकर भराई करना थी वहां विशुद्ध काली कपासी (मुरमुरी) मिट्टी से भरकर उस पर सीमेंट की दस से.मी. की परत के स्थान पर 6.5 से.मी. लेकर 7,7.5 से.मी. की क्रांकीट की गई है। जो नहर के चलने और पानी के दबाव से 3 से 6 माह में फट जाने की पूरी संभावना है। पर इस जालसाज हरामखोर ठेकेदार कर्णसिंग ने सारे इंजीनियरों जिसमें खासतौर इंग्ले जो अब वहीं अधीक्षण यंत्री बन गया है, राठी उस वक्त का अधीक्षण यंत्री अब धूर्त चौरसिया है अधीक्षण यंत्री से लेकर मुख्य अभियंता उस समय रघुवंशीवाद में राठौर, और अब एम.एल. गुप्ता हैं। को पर्याप्त महीना बांटकर ताले रखे थे और हैं। इसलि समय माया की इन सच्चाइयों को चित्र सहित छापने के बाद भी किसी भी नीचे से लेकर ऊपर तक किसी भ्रष्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की है। शिकायतों को लेकर मुख्य तकनीकी परीक्षक तिवारी व अन्य लोगों की टीम 18-12-08 को भी पहुंची थी, मोटे भ्रष्टों ने कुछ टुकड़े इनको भी उछाल दिए और सब ठीक हो गया।

इससे जुड़ी इंदिरा सागर नहरों के सनावद मुख्य अभियंता कार्यालय में इंदिरा सागर नहरों के साथ संभाग 8 में ओंकारेश्वर नहरों का भी कुछ हिस्सा शामिल किया गया, कां.अं. आरघ अपने संभाग में 5 वर्षों से ज्यादा समय से अपने भ्रष्टाचार, लूटों और लुटाओं के दम पर जमे हुए हैं।इनके अंतर्गत बिहानी और कर्णसिंग के अधिकांश ठेकों के कार्य अधूरे हैं। सही मायनों में ये इन ठेकेदारों की कठपुतली बन उनके फायदे के कार्यों को करने में तल्लीन रहते हैं। इस का.अ. आरघ ने करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार से कमाई की है यही अभियंता विधायकों, सांसद, पत्रकारों, अपने वरिष्ठ अभियंताओं से लेकर अध्यक्ष और मंत्री तक को खुश रखता है। इसलिए 5वर्षों के बाद भी डंटा है।

ओंकारेश्वर नहरों का कार्य चूंकि अब मुख्य अभियंता इंदौर के क्षेत्र में आ गया है। जिससे नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण के इंदौर और खेड़ी के अधीक्षण यंत्री कार्यालय में कुछ रौनक भी भ्रष्टाचार के धन से आ गई है।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण की सभी नर्मदा परियोजनाओं में ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी इंजीनियरों, ठेकेदारों से लेकर मंत्री, संत्री सब मिलकर 50% शुद्ध रूप से डकारने में लगे हैं, इसलिए कोई भी कार्य न तो गुणवत्ता पूर्ण, स्तर और चित्रांकन के हिसाब से हुआ न ही कोई भी कार्य समय पर पूरा हुआ। अन्यथा 23-10-08 को जब इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था तब पूरी पूर्वी-पश्चिमी निमाड़ अर्थात खंडवा, खरगोन, बड़वानी का अधिकांश कृषि क्षेत्र को सिंचित होकर 12 माह फसल पैदा करने वाला बनकर दूसरा पंजाब, हरियाणा बन जाना था, पर यहां तो भ्रष्टाचार के चलते कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका।

लोकस्थ...

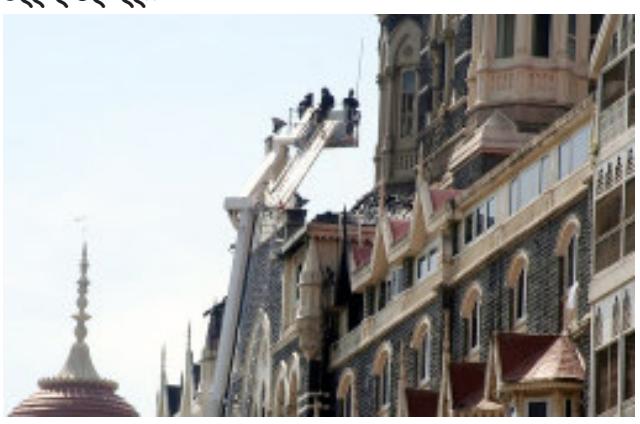

इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और प्रदेश के हर जिले से लेकर पूरेप्रदेश के नगरों, महानगरों में तक मुस्लिम आतंकवादियों को इन्हीं कांग्रेसी धूर्तों ने पाला, पोसा और बड़ा किया है जिसमें न केवल म.प्र. पुलिस वरन पूरे प्रदेश की पुलिस भी शामिल है। तो सबसे पहले अपने गिरेबां में चढ़ी कालिख तो साफ करो, फिर पाकिस्तान से युद्ध करने की बात करो अब जबकि दोनों देशों में बसों से आना जाना वर्षों से चल रहा है तो यहां के आतंकवादियों की मुस्लिम आतंकवादियों से सांठगांठ होगी ही।

मुम्बई के होटल ताज में 9 आतंकी मार दिए। पाकिस्तानी पकड़ा गया,हाटेल ट्राइटेंड, नरीमन हाऊस के आतंकियों का क्या हुआ, कहां गए, वो दूसरा ताज में भी 24 आतंकी घुसे थे। 14 को कहां भगाया, छुपाया आखिर 10 आतंकी पूरे 700 कमरों की होटल पर कैसे कब्जा कर सकते हैं। होटल ताज में 563 कमरे यात्रियों के लिए, तो फिर किचन, स्टोर, प्रबंधन, कर्मचारियों के आवास, हाल, डांस हाल, अर्थात 700 कक्षों वाले इस होटल पर मात्र 10 ने ही इतना कहर बरपा दिया। फिर 60 घंटे तक जो उन्होंने गोला बारूद उपयोग किया वो अगले पिछले दरवाजों से भी अंदर ले जाते समय सब सो रहे थे। चलिए प्रश्नों के समंदर में गोता लगाने से बेहतर है पाकिस्तान और भारत की सीमाओं पर जमा होते सैन्य जमावड़े और युद्ध की तरफ बढ़ते टैंकों, तोपों सैनिकों, लड़ाकू विमानों के चिंघाड़ती उड़ाने की तरफ जहां भारी हलचल है, चलते हैं। वैसे ये चुनाव जीतने का ही स्टंट मात्र है। क्योंकि केंद्र की सत्ता में बैठे कांग्रेसी सत्ताधीशों को तो अंग्रेजों ने घुट्टी में पिलाया था हमने फूट डालो और राज करो पर न केवल पूरे भारत पर

पेज 1 से जारी

कब्जा कर राज किया है। तुम भी करो, की तर्ज पर पहले कांग्रेस स्वयं मुस्लिम वोटों के लिए स्वयं आतंकीयों की जननी, आतंकियों को जन्म देकर पालना बंद करे, स्वयं आईएसआई के साथ मिलकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देना स्वयं रोके और आतंक को सत्ता चलाने का और पाने का हथियार स्वयं फेकें फिर पाकिस्तान पर आक्रमण करे।

जहां तक अमेरिका का सवाल है तो वह तो शुरू से ही दक्षिण एशिया को अपना हथियारों से लेकर कंडोम तक के बेचने का बाजार समझता है। वह दोहरी नीति खेल रहा है। वो तो चाहता है युद्ध हो और उसके हथियार व अन्य सैन्य सामग्री का बाजार गर्म हो और उसकी मंदू दूर हो। इसके बंबई के ताज होटल कांड के अतिरिक्त जितने भी आतंकी घटनाएं हुईं उनके कितने सबूत कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखे। मुम्बई कांड में भारत के पास अजमत कसाब के अतिरिक्त और क्या ठोस सबूत है वह न तो पाकिस्तान को बताना चाहता है न ही स्वय़ं की जांच में मिले तथ्यों को इंटरनेशनल पोलिस अर्थात इंटरपोल से विनिमय करना चाहता है, क्योंकि हमारी कांग्रेस सरकार को मुस्लिम वोट चाहिए है, फिर अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने जनता व मीडिया का ध्यान बंटाने का हथियार भी वह कैसे अपने हाथों से बर्बाद कर दे, जबकि इस सटीक हथियार से वह पिछले 30वर्षों से शासन करती आ रही है।

साप्ताहिक समय माया

शिवराज मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विभाग

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही शनिवार देर रात सभी मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण कर दिया है। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने पास सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन सहित वे सभी विभाग रखे हैं जो किसी मंत्री के पास नहीं है। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल गौर को नगरीयप्रशासन तथा गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, राघवजी को वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, बीस सूत्र कार्यान्वयन और वाणिज्यिक कर, जयंत मलैया को जल संसाधन, आवास एवं पर्यावरण, कैलाश विजयवर्गीय को वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, सूचना प्रोद्यौगिकी, सार्वजनिक उपक्रम, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामोद्योग एवं संसदीय कार्य विभाग दिए गए हैं। इसी प्रकार गोपाल भार्गव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अनूप मिश्र को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और ऊर्जा जगदीश देवड़ा को गृह, परिवहन तथा जेल लक्ष्मीकांत शर्मा को संस्कृति, जनसम्पर्क, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व जनशिकायत निवारण, नागेंद्र सिंह नागौद को लोकनिर्माण, अर्चना चिटनिस को उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग दिया गया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कैबिनेट मंत्री जगन्नाथसिंह को आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण, डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया को कृषि मछलीपालन, पशुपालन एवं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, गौरीशंकर बिसने को लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता तथा तुकोजीराव पवार को पर्यटन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) करणसिंह वर्मा को श्रम, राजस्व और पुनर्वास, पारस जैन को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, राजेंद्र शुक्ल को वन, जैव विविधता एवं प्रौद्योगिकी खनिज एवं विधि विधायी कार्य एवं रंजना बघेल को महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय विभाग दिया गया है। राज्यमंत्री नारायणसिंह कुशवाह को गृह, परिवहन और जेल, कन्हैयालाल अग्रवाल को सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास और विमानन, हरिशंकर खटीक को आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण तथा देवीसिंह सैयाम को पंचायत एवं ग्रामीण विकास से जोड़ा गया है।

भाजपा के घोषणा पत्र में 412 बिंदुओं पर जोर

भोपाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने अपनी दूसरी पारी शुरू करने के तुरंत बाद मुख्य सचिव राकेश साहनी को भाजपा का घोषणा पत्र थमाते हुए निर्देश दिए कि उसका पालन तुरंत शुरू करवा दिया जाए। प्रदेशभर के अधिकारी, कर्मचारी अब भाजपा के घोषणा पत्र को पढ़ने में लग गए हैं और कलेक्टर ने भी 100 दिनी कार्ययोजना की तैयारी शुरू कर दी है। भी तक मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को कमजोर प्रशासनिक पकड़ वाला मुख्यमंत्री माना जाता था, मगर अब वे दूसरी पारी में पूरे आत्मविश्वास से दिख रहे हैं और अधिकारियों को भी अपने तेवर से अवगत करा चुके हैं। इतना ही नहीं कुर्सी संभालने के तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले काम यही किया कि मुख्य सचिव को भाजपा का घोषणा पत्र सौंप दिया और कहा कि इस पर तुरंत मैदानी कार्यवाही होना चाहिए। मुख्य सचिव राकेश साहनी के निर्देश पर सभी विभागों के आगा अधिकारी 100 दिनी कार्ययोजना बनाने में जुट गए हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 412 बिन्दुओं के विकास से संबंधित तय किए हैं। गांव-गांव में शासन की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई जाएगी और उन पर अमल भी करवाएं जाएंगे।

आखिर अधिकांश दागी पुनः विधायक बन ही गए

कांग्रेस-भाजपा दोनों ही आपराधिक गिरोह

भोपाल। प्रदेश के दोनों ही राजनीतिक दलों ने जनता से स्वच्छ प्रशासन देने का वादा किया था, इसलिए अपराधियों को टिकट नहीं देने की बात भी बड़े जोर-शोर से उठाई गई थी। इसके विपरीत दोनों ही पार्टीयों ने अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को न केवल टिकट दिए वरन उसमें से अधिकांश लोग चुनकर पुनः विधानसभा में भी पहुंच गए। दोनों ही पार्टियों के एक सैकड़ा से ज्यादा विधायक व मंत्री ऐसे हैं जिन्हें पुलिस रिकार्ड में न केवल फरार घोषित कर रखा है, वरन वे नियमित रूप से विधानसभा में भी अपनी हाजिरी लगाते हैं। परंतु पुलिस को नहीं दिखते। विधायक विजय शाह तो पूर्व में ऐसा मंत्री था जो कई अपराधों में खंडवा जिला कोर्ट में फरार घोषित है पर बकायदा वे पुलिस से मंच पर खड़े होकर सलामी ले रहे थे। दिसम्बर 08 को 13वीं विधानसभा में चुने गए विधानसभा सदस्यों में भी दोनों कांग्रेस और भाजपा को एकही सिक्के के दो पहलू यूं ही नहीं कहा जाता। दोनों ही पार्टियों के तेरहवीं विधानसभा में चुनकर आए जनप्रतिनिधियो का आपराधिक रेकार्ड है। इस मामले में दोनों ही दल चोर-चोर मौसेरे भाई हैं, लेकिन जहां तक गंभीर अपराधों का मामला है, कांग्रेस का कद ऊंचा है।

चार दर्जन से भी ज्यादा विधायकों पर गलत काम करने, दंगे भड़काने, दंगों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने, शासकीय कर्मचारियों को मारने-पीटने आदि के मामले लंबित हैं। ये तो साधारण कारनाम हैं। इन पर हत्या, हत्या का प्रया, धोखाधड़ी, डकैती के भी मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ पर तो भ्रष्टाचार निरोधी कानून के अंतर्गत मुकदमें भी चल रहे हैं।

पूर्व मंत्री और पिछोर से कांग्रेस के विधायक के.पी. सिंह पर अपहरण, डकैती आदि के मुकदमे लंबित हैं। उन्हें लोग सम्मान से 'काकाजू' कहते हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और चार सौ बीसी के मामले चल रहे हैं। ये लहार की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी हरवंशसिंह के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज तो है। इन्हें सुमावाली की जनता से चुना है।

राजगढ़ के **शेष पेज 2 पर**

घर ले जाकर बदले जाते हैं नमूने

10% नमूने मिश्रित वो होते हैं, जिनसे मामला नहीं जमता

म.प्र. खाद्य एवं औषधि अपमिश्रण विभाग

इंदौर। म.प्र. खाद्य एवं औषधि प्रशासन के इंदौर कार्यालय में अब खाद्य निरीक्षकों की संख्या मात्र 9 हो चुकी है। समयमाया के लंबे प्रयासों से इंदौर में वर्षों से बैठे एक खाद्य निरीक्षक से बढ़कर 9 तो अवश्य हो गये, परन्तु आबादी के हिसाब से पूर्व की तरह कम से कम 15 निरीक्षक होना ही चाहिए, एक खाद्य निरीक्षक का मासिक लक्ष्य मात्र 10 नमूने लेना ही होता है।

कुछ ही दिनों पूर्व दैनिक भास्कर में इस विभाग से संबंधित जो समाचार छपा था कि 90 प्रतिशत अपमिश्रित नहीं पाये जाते हैं जैसा कि वहां के पूर्व के खाद्य निरीक्षक सचिन लोंगरिया ने बताया था, विभाग में नमूने लेकर भेजने तक उन्हें सभी खाद्य निरीक्षक घर पर ले जाकर रख लेते हैं। बेशक उस कार्यालय में स्टाफ को बैठने तक के लिए पर्याप्त फर्नीचर भी नहीं है, इसके विपरीत गंभीर परिस्थितियां इतनी भी गंभीर नहीं है कि नमूने घर पर ले जाना पड़े।

वास्तविकता में नए पुराने सभी निरीक्षक इन नमूनों को घर ले जाकर तब तक सील बंद नहीं करते जब तक खाद्य विक्रेता घर पर आकर लेन-देन की बात नहीं कर लेता यदि इन हरामखोरों रु. 10 हजार से लेकर विक्रेता की क्षमता के अनुसार सौदा नहीं पटता तो ही तत्काल लिया गया नमूना जैसा लिया गया था वैसा ही कानूनी खानापूर्ति कर भेज दिया जाता है। सौदा पट जाने लेन-देन हो जाने पर वह नमूना बदलकर गुणवत्ता युक्त नमूना ही प्रयोगशाला को भेजा जाता है। जो कि स्वाभाविक है अपमिश्रित न पाये जाने के कारण नकारात्मक परिणाम देते हैं।

आठ नये नियुक्त खाद्य निरीक्षकों को आये अभी जुम्मा-जुम्मा 8 महीने भी नहीं हुए है, पर सब अवैध वसूली विशेषज्ञ बन चुके होकर दोनों हाथ वसूली में लग चुके हैं। यही हाल उज्जैन में खाद्य निरीक्षक पथरोल व अन्य खाद्य निरीक्षकों का भी है। जब तक पथरोल उज्जैन में अकेला निरीक्षक था, प्रतिमाह रु. 4 से 5 लाख महीना नमूने लेने के बहाने अकेला ही वसूल रहा था, अभी जो खाद्य निरीक्षक कुछ ही महीनों पूर्व उज्जैन में नियक्त हुए है उनका गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण वे अभी प्रशिक्षण में है।

देवास में श्रीमती लोंगरिया व अन्य नये आए खाद्य निरीक्षक है, उनका भी गजट नोटिफिकेशन कुछ का न होने के कारण वे भी प्रशिक्षण अवधि पूरी कर रहे हैं। जिनका गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, वे सभी इंदौर, उज्जैन, देवास, खंडवा, खरगोन, शाजापुर, रतलाम, सीहोर के साथ ही पूरे प्रदेश में नमूनों की आड़ में अवैध वसूली का भी कार्य दोनों हाथ शुरुकर चुके हैं। भ्रष्ट और मिलावटी खाद्य सामग्री, निर्माता पेकर्स, आपूर्तिकर्ता, डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स से लेकर अंतिम छोर का फुटकर विक्रेता जो मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक रु. दो-पांच हजार से लेकर उसकी क्षमता तक वसूली देते हैं। खाद्य निरीक्षकों की बढ़ती संख्या से थोड़े से परेशान अवश्य है, परन्तु निश्चित है। क्योंकि जितने भी हो आते ही साथ हरामखोरी की दाड सबकी आ ही जाती है। शासकीय पद पर बैठते ही साथ, जितनी साइज की हो उतना टुकड़ा डालते ही साथ लार टपकाना बंद और चल भाई अगला घर देख, दूसरे का नमूना ले जहां से नहीं मिल रहा है। ये भी सभी नए-नए मूर्गों की तरह ज्यादा और जोर से बाग इसलिए ही दे रहे हैं ताकि सबको महीना मिलने लगे।

औषधि विभाग

- औषधि निरीक्षक डी.के. जैन का निलंबन रु. 10 लाख के बाद समाप्त हो गया है, पुनः दवा बाजार में पदस्थ हो चुके हैं।
- इंदौर के औषधि विभाग के कई नये औषधि विक्रेताओं के थोक व फुटकर की अनुज्ञप्तियां लंबित पड़ी है, क्योंकि इनकी अनुशंसा पर उच्च अधिकारियों ने हस्ताक्षर करने का शुल्क रु. 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया है, लेन-देन की इस मशक्कत में औषधि निरीक्षक दरबार में दरबार के घर जाकर हाजिरी और सौदा पटाने का प्रयास कर चुके हैं। पर समाचारों के अनुसार रुपए 25000/ – से कम में सौदा नहीं पट रहा है।
- औषधि निरीक्षक डी.के. जैन के निलंबन काल में औ.नि. वृंदनानी को प्रभार मिल गया था। समाचारों के अनुसार उसने रुपए 10 लाख से ज्यादा की वसूली कर अपमना कोटा पूरा कर लिया है।
- कई वर्षों से जमें औ.वि. परिहार ने शीघ्र ही ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की घोषणा कर दी है तो 30/06/09 तक विभाग त्याग देंगे। उन्होंने पिछले 20 वर्षों से ज्यादा समय से इंदौर में रहकर इतनी वसूली कर ली है कि उन्हें पेंशन न भी मिले तो बाकी बची जिंदगी वो शान से गुजार लेंगें।

खाद्य विभाग के धूर्तों को महीना

गैस टंकियों में पानी

अग्नि गैस एजेंसी की टंकी में पानी के साथ ही सभी कुकर्म

इंदौर। गैस उपभोक्ता को हरामखोर डीलर कैसे-कैसे हथकंडों से लूट रहे हैं। पिछले कई वर्षों से दैनिक समाचार पत्रों के साथ ही 'समय माया' भी इनकी जालसाजियों और म.प्र. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के धूर्त नियंत्रक परमार और वहां वर्षों से बैठे शमी, मीना नायक, शुक्ला, सेंगर, सहायक नियंत्रक, खाद्य निरीक्षकों को 20 पेट्रोल पम्पों, 25 गैस विक्रेताओं, 400 के लगभग राशन दुकानों से लेकर मिट्टी के तेल के हॉकरों तक से रुपए 100 से 500 तक प्रति महीने की वसूली कर ये मक्कार श्वानों की फौज आराम से तान के सोती है।

यही कारण है कि अकेले इंदौर शहर के 25 से ज्यादा एलपीजी गैस वितरक रुपए 10000/- प्रति माह निरीक्षकों से लेकर नियंत्रक तक को बांट कर सभी प्रकार की जालजासियां खुले में करकर भी इन सफेदपोश गैस वितरकों का कहीं कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जबकि ये गैस वितरक खुलकर उपभोक्ताओं के साथ हर प्रकार की जालसाजियां करते हैं। गैस सिलेंडरों से गैस चोरी करने बदले में 14 ली. के सिलेंडर में 10 से 12 ली. तक पानी भर कर बेचने, गैस की कालाबाजारी करने, घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर व्यावसायिक सिलेंडर में भरने तक के सारे कारोबारों को करने के बाद भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के हरामखोरों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। नियंत्रक परमार से पूछताछ करो तो मुझे मालूम नहीं है। फाइलें देखना पड़ेंगी। संबंधित से पूछना पड़ेगा तो ये श्वान किस बात का वेतन ले रहे हैं। जबकि आपस में बात करेंगे तो सब इनके भेजे से तत्काल निकल आएगा। अगर कभी जिलाधीश किसी जांच कीबाच भी करेगा किसी उपजिलाधीश या सहा. जिलाधीश के साथ टीम गठित की जाएगी तो ये खाद्य विभाग में बैठे हरामखोर सभी पेट्रोल पम्पों, गैस वितरकों, राशन दुकानों को बता देते हैं, ताकि सब जागृत हो जाएं। राशन दुकान वाले तो अधिकांश ताले लगाकर भाग जाते हैं। जिनकी दुकानें खोलकर रखना मजबूरी होती है वो अपने हिसाब किताब ठीक-ठाक कर लेते हैं। अब जबकि शक्कर, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल सभी बाजार में मंहगा है, खुलकर गांवों की सहकारी समितियों से लेकर शहरों तक के सभी सहकारी उपभोक्ता भंडार खुले में ब्लैक मार्केटिंग कर दोनों हाथ वसूली कर रहे हैं। ये हालात इंदौर के साथ धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, के साथ उज्जैन,देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच सभी जिलों के हैं। सभी जिलों के खाद्य अधिकारी खुलकर पेट्रोल पम्पों, गैस पम्पों, गैस वितरकों, राशन दुकानों से दोनों हाथ वसूली कर रहा है पूरा स्टॉफ तो फिर कौन पूछेगा कि गैस डीलर टंकियों में पानी भर कर बेच रहा है। गैस डीलरों की कम गैस देना, ब्लैक में बेच देना, टंकियों में पानी भरना, 2 दिन से लेकर 15 दिन से महीने भर तक गैस न देना उनके नम्बर की गैस दुकानों और व्यावसायिक उपयोग में बेच देना।

अग्नि गैस का मालिक आई.जी. अग्निहोत्री का लड़का है। फिर उसका एक रिश्तेदार सहा. खाद्य अधिकारी पी.के. शुक्ला वर्षों से इंदैर में जमा है, उसके विरुद्ध की गई हर शिकायत जांच को वो वहां बैठकर बचा लेता है। इसके सिलेंडर से पानी निकलते हुए राज टी.वी. पर भी दिखा दिया गया है। परंतु इस हरामखोर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके खिलाफ अनेकों बार उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन भी किए। समाचार पत्रों में भी छपा, जबकि इस गैस एजेंसी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, इससे ज्यादा बात करो तो यहां बैठी धूर्तों की फौज गैस कनेक्शन ट्रांसफर करवाने की बात करती है। यही हाल 25 गैस वितरकों का है। गैस ओ इंडेन वाले ने तो ग्राहकों को अभी तक डायरी ही नहीं दी है। जब भी उपभोक्ता कहता है, यहां बैठी फौज कह देती है कंपनी से ही नहीं आई इसकी आड़ में इसका मालिक लाखों रुपए की गैस हर माह ब्लैक में बेच खाता है। दूसरे गैस सिलेंडर की जालजासियों में इन्होंने दूसरे गैस सिलेंडर से लोगों को कनेक्शन बांट रखे हैं। जो वर्षों से ब्लैक में चलाए जा रहे हैं। व्यावसायिक उपयोग में खाद्य विभाग में तो महीना पहुंचता रहे सब ठीक-ठाक रहता है।

भ्रष्टाचार का अरबों रुपए पहुंचता है संचानालय और स्वास्थ्य आयुक्त को

डॉ. पंडित का पांडित्य है भ्रष्टाचार में

पूरे प्रदेश में न केवल दवा खरीदी वरन हर कदम है लूट व वसूली का तांडव

पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में हर कदम पर वहां पदस्थ डॉक्टरों, नर्सों से लेकर कमाउंडर और वार्डबॉय की वसूली से लेकर म.प्र. के विंध्याचल में स्थित स्वास्थ्य संचानालय और स्वास्थ्य आयुक्त तक पूरे प्रदेश से अरबों रुपए का भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। शासन की गरीबों की स्वास्थ्य योजनाओं के नाम पर खुलकर झूठे व्हाउचरों के सहारे 60% तक धन डकारा जा रहा, जिसमें हर जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने अधीनस्थों और साथ ही निजी नर्सिंग होम्स, हास्पिटल से लेकर निजी मेडिकल कालेजों के साथ मिलकर केंद्र व राज्य सरकार के स्वास्थ्य के बजट की पूर्ण चिकित्सा कर रहे हैं।

इंदौर का मु.स्वा. व चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंडित का भ्रष्टाचार को पांडित्य का ज्ञान इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये हरामखोर भविष्य निधि की रकम डकारने के चक्कर में यहां से देवास भेजा गया था, परंतु उसी भ्रष्टाचार के धन के दम पर पैसे खर्च कर पुनः इंदौर लौट आयाहै, दवा खरीदी कांड तो उसकी लूट का छोटा सा हिस्सा है। जिसमें इसने अपनी सीमा के बाहर जाकर रुपए 60 लाख की अनाप-शनाप अनावश्यक दवाएं केवल पनी कमीशन खोरी के लिए खरीदी। इसी प्रकार मरीजों के भोजन के नाम पर बिस्कुट खरीदी कांड किया।

जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर तहसील स्तर के चिकित्सालयों में दवाओं के अतिरिक्त चिकित्सालयों में लगने वाली अन्य सामग्रीयों में चादर, तकिये, कंबल, गद्दों अन्य चिकित्सालयों की आवश्यक सामग्रियों में सीधे ल.उ.नि. की आपूर्तिकर्ता इकाइयों के सीधे करोड़ों रुपए के बिल भर पास होते रहे हैं। सामग्रीयों का कहीं अतापता नहीं है। यदि सामग्री आपूर्ति की भी जाती है तो चूंकि मुख्य स्व. एवं चिकित्सा अधिकारी ही महाभ्रष्ट और जालसाज हैं तो दूर दराज के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों और तहसीलों और विकासखंडों के साथ ही शहरों के चिकित्सालयों के डॉक्टरों, कर्मचारियों, नर्सों व अन्य अधिकारियों से कैसे उम्मीद जा सकती है कि वो ईमानदारी से कार्य करेंगे वो भी अधिकांश सामग्री बेचकर खा जाते हैं और पुरानी सामग्रीयों को भंडारगृह में जमा या अस्पताल के स्कंध में दिखा दी जाती है।

वर्तमान में प्रदेश में जिला स्तर पर बीमारी सहायता निधि में रुपए 25000 से रुपए 150,000/- दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में 20000/- तक वित्तीय सहायता जननी सुरक्षा योजना में गर्भवती को ग्रामीण क्षेत्रों से लाने वाले को रुपए 600, गर्भवती को रुपए 1400 सौ, शहरी में गर्भवती को रुपए 1000 व लाने वाले को रुपए 200 के नाम विजयराजे जननी कल्याण बीमा योजना में रुपए 5000 तक, मृत्यु होने पर व इलाज के लिए रुपए 1000 के नाम पर भी अकेले इंदौर जिले में ही निजी नर्सिंग होम्स वाले चिकित्सा के ग्रामीणों, गरीबों से तो अपने पैसे वसूल तो करते ही साथ ही इस डॉ. पंडित के साथ मिलकर शासकीय धन भी सभी खानापूर्तियां करके डकार जाते हैं। यह सौदा सीधा-सीधा 50%-50% पर पिछले दो वर्षों से चल रहा है। निजी नर्सिंग होम्स, चिकित्सालयों में वहां के डॉक्टर्स, वहीं उन गरीबों, मरीजों से सारे शास. खानापूर्ति के प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करवा कर ग्रामीणों को विदा कर देते हैं। बाद में इस मु.चि. स्वास्थ्य कार्यालय के स्टाफ के सात मिलकर हर वर्ष करोड़ों रुपए की जालसाजियां कर धन डकारा जा रहा है। इसकी सूचनाएं न केवल इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी,खंडरा, खरगोन, बुरहानपुर के साथ ही उज्जैन, उज्जैन संभाग के देवास, रतलाम, शाजापुर, नीमच, मंदसौर से भी लगातार आ रही हैं।

इसकी जानकारी सूचना के अधिकार में प्राप्त करने के लिए संभाग प्रभारी संयुक्त संचालकों को इंदौर-उज्जैन में पत्र भेजा गया था, परंतु संयुक्त संचालक इंदौर-उज्जैन भी हैं तो भ्रष्टों के वरिष्ठ महाभ्रष्ट उन्होंने केवल औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए पत्र अवश्य अंतरित कर दिया जिसके जवाब में अकेले इस भ्रष्टाचार के पांडित्य ने चमकाने के लिए श्री अजमेरा को रुपए 4 लाख 58 हजार की धन राशि जमा करने का नोटिस भेजा। ये मिठुआ डॉ. पंडित चूंकि चारों तरफ से चिकित्सा विभाग में प्राप्त राज्य सरकार का धन केंद्र सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ आदि अनेकों योजनाओं का विभिन्न मदों का धन डकार रहा है, जिसमें नर्सिंग ट्रेनिंग, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, मलेरिया , टीबी, परिवार नियोजन, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, एड्स, टीकाकरण, आशा स्वास्थ्य जागरुकता मिशन, जननी सुरक्षा योजना, जिला स्वास्थ्य सूचना शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि के नाम पर अरबों रुपए की शासकीय निधि में ये बंदे दोनों हाथों से भ्रष्टाचार कर रहा है तो आखिर कैसे जानकारी दे दें। स्वाभाविक है इन सारी योजनाओं का पूरे प्रदेश का धन विंध्याचल स्थित स्वास्थ्य संचानालय में प्रतिदिन अरबों रुपए पहुंच रहा है। इसके बाद भी डॉ. पंडित ने कर्मचारियों के ही भविष्यनिधि में जाली दस्तावेजों से करोड़ों रुपए निकालकर डकार लिए। एक साधारण अनुमान के अनुसार हर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी हर दिन लाखों रुपए की रिश्वत और भ्रष्टाचार से धन डकार लेता है। स्वाभाविक है सभी स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारी भी इसमें हिस्सेदार होते हैं, इसलिए सब चुपचाप रहते हैं। कुछ वर्षों पूर्व बड़वानी में हजारों रुपए की प्रतिदिन होने वाली फोटोकापी के व्हाउचरों से डकारे गए रुपए का मामला प्रकाशित किया था।

लोकायुक्त के भ्रष्टों को भी धन पहुंचता रहता है। इसलिए वो हरामखोरों की फौज कैसे उसमें हाथ डाले। सूचना के अधिकार में भी दी गई अपीलों में चूंकि अच्छेखासे धन का लेनदेन मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त कर डालते हैं, इसलिए वो हरामखोर तथ्यों की वास्तविकता को नजर अंदाज कर आवेदकों के विरुद्ध निर्णय देते रहते हैं। इसलिए ये हर स्वास्थ्य विभाग के हरामखोर अपने तरीकों से आवेदकों को नचाकर जानकारी देने से बचते रहते हैं।

सभी बैंक है सफेदपोश जालसाज डकैतों के अड्डे

बैंकों में कम्प्यूटरों, ट्रांजेक्शन से धड़ल्ले से ग्राहकों से हो रही धोखाधड़ी

पूरे भारत में बैंकिंग, व्यवसाय पूर्णतः सफेद पोश जालसाजों का अड्डा बनता जा रहा है। यहां के अदने से कर्मचारियों से लेकर निजी सहकारी, सरकारी बैंकों में प्रबंध संचालक व अध्यक्ष तक अपनी हैसियत, मौके, पद व अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों से समन्वय के हिसाब से बड़ी-बड़ी जालसाजियों को अंजाम दिया जा रहा है। पर बैंकों में बैठे अधिकारी प्रबंधक सब चूंकि भ्रष्टाचार में आकंठ गोते लगा रहे हों तो ग्राहकों की जालसाजी की शिकायतों, बैंक चेक, ऋण, आवर्ती, चालू, साख आदि में जमा किये धन के साथ, चेक, ड्राफ्ट आदि भी संबंधित के खातों में जमा न होकर वहां बैठे जालसाजों की फौज उसे स्पेंस खाते में जमा करती है, बाद में बात पुरानी होने पर वह ग्राहक के खाते में जा रकम उचककर स्टॉफ कर्मियों के खातों में पहुंच जाती है, मूल व्हाउचर फाड़कर रही की टोकरी में डाल उस पर नया व्हाउचर चिपकाकर सीधे ही जालसाज श्वानों द्वारा अपने किसी भी परिचित या स्वयं के वेतन खाते में अतिरिक्त अन्य खातों में डालकर डकार लिया जाता है।

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की फडनीस कॉलोनी शाखा में बैठा स्टॉफ के साथ ही वहां का प्रबंधक उन बत्तमीजों का गिरोह है जो ग्राहक को बात-बात में झिड़की देता है। यहां के हरामखोरों से समाशोधन के चेकों को स्वीकार करने उस पर हस्ताक्षर व सील लगाने के लिये कहा गया तो कहा गया डिब्बे में डालो या विश्वास नहीं है, तो खाता बंद कर लो इन हरामखोरों के दिमाग इतने सड़ चुके हैं कि रिजर्व बैंक के स्पष्ट आदेशों के बाद भी चेक जमा करने की पर्चियों पर हस्ताक्षर करने और सील लगाने में इन जालसाजों के प्राण निकलने लगते हैं। यही हाल इस बैंक की अधिकांश शाखाओं के हैं। वहां के जालसाजों ने समयमाया के 3000/- के चेकों को खाते में जमाकर न स्वयं डकार लिया, वहां मीना नाम की स्टाफ क्लर्क कम्प्यूटर पर ताश खेलती रहती है, आलम यह है कि इन स्टेट बैंक व उसकी सहयोगी बैंकों के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के भी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक अधिकांश भारी खुले में जालसाजियां कर रहे हैं। इसके विपरीत इन जालसाजों को पकड़ में आने के बाद भी कार्यवाहियां न हो पाने के कारण इन श्वानों की चमड़ी भारी मोटी हो चुकी है। ये जिस ग्राहक की रोटियां खाते हैं जालसाजी करने और पकड़ने जाने के बाद भी ग्राहकों के साथ मारापीटी करने तक से नहीं चूकते हैं।

स्टेट बैंक व राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहकों से शुल्क तो रिजर्व बैंक ने अनाप-शनाप बढ़ा दिये, बात-बात में कटौतियां की जाती है। इसके विपरीत ग्राहकों को सूचनाएं तक भी नहीं दी जाती है। 60% तक ऋणों की स्वीकृति जाली दस्तावेजों के आधार पर 10 से 20% तक कमीशन खाकर खुले में की जा रही है, स्वाभाविक हैं, बैंक में डूबते ऋणों के प्रतिशत में भारी बढौत्री होने के बाद भी, सीबीआई जांच तक बैंकों 0.5% मामले भी ऐसी जांचों के लिए नहीं पहुंचाये जाते हैं।

प्रबंधन में बैठे श्वानों को तो वैसी भी काफी मोटे वेतन मिलने के बाद भी जालसाजियों से कोई नहीं चूकता जालसाजियों, चेकों को डकार जाने, खातों में धन जमा होने के लाखों शिकायतें हर बैंक और उसकी शाखाओं की होने के बाद भी, बैंक कर्मचारियों के निलंबन, सेवा समाप्ति व अन्य दंडों की तो दूर, यदि महिला कर्मचारी हैं, तो वर्षों तक साथ में काम करते-करते उनके अपने प्रबंधकों, श्रमिक संघों से अपनी कमनीयता और प्रगाढ़ संबंधों के चलते न केवल बची रहती है बल्कि के तरफ तो बैंक में बत्तमीजियां, जाजसाजियां करती हैं, फिर अपने यारों के साथ ग्राहकों की शिकायतों पर उनसे ग्राहकों को धमकाना, मारना, पिटवाना तक करती हैं।

हर ग्राहक इनकी प्रताड़नाओं, बत्तमीजी पूर्ण व्यवहार से परेशान होने के बाद भी जीवन की आपाधापी इतना उलझा रहता है, कि तो इनकी शिकायतें नहीं कर पाता, जिससे इन मक्कार धूर्तों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि इनकी बत्तमीजियां सिर चढ़कर बोलने लगती है। बात-बात में ग्राहकों को खाता बंद करने की धमकी देते हैं।

बैंकों में हुए भारी कम्प्यूटराइजेशन ने जालसाजियों को न केवल बढ़ाया है, वरन जालसाजियों को पकड़ने में भी भारी परेशानियां उठानी पड़ती है। पैसा जालसाजी से इधर-उधर चले जाने पर बिना पुलिस शिकायत के कोई भी हरामखोर बैंकर्स सुनने को तैयार नहीं होते।

ग्राहकों को चाहिये कि बैंकर्स की जालसाजियों पर सीधा दस्तावेज इकट्ठे कर पुलिस में एफआईआर संबंधित थाने में करें, थाने पर भी सुनवाई या जांच न होने पर बिना विलंब किये इन्हें न्यायालयों में खींचकर खड़ा करने में बिल्कुल भी न हिचकिचाये। उपभोक्ता न्यायालयों में भी सेवाओं, प्रताड़ना, परेशानियों के विरुद्ध सीधी कार्यवाहियां करें, उपभोक्ता न्यायालयों में वकील की जरूरत भी नहीं पड़ती है।

जहां तक बैंकर्स की शिकायतों के लिए उनके प्रधान कार्यालयों में शिकायत सेल होता है, परन्तु इनसे न्याय की उम्मीद तो दूर ये सब ही एक ही थाली के चट्टे-बट्टे होने के कारण ये सब भी अपने स्टाफ को ही बचाते हैं। जहां तक हर प्रदेश में बने रिजर्व बैंक के लोकायुक्त का सवाल है तो ये भी मोटी चमड़ी के हैं। व्यर्थ समय और पैसा बर्बादी है।

मनमोहन और रिजर्व बैंक भू-माफिया और पूंजीपतियों की कठपुतली

गृह ऋणों और कार ऋणों पर छूट का षड्यंत्र

राष्ट्र में आर्थिक मंदी के नाम पर भू-माफियाओं, कार निर्माताओं और पूंजीपतियों की कठपुतली बन न केवल नाच रहे हैं, बल्कि शासकीय बैंकों में जमा जनता का 200 अरब रुपए फिर जालसाज भू-माफियाओं, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा। वह भी 5 से 8% ब्याज पर, एक तरफ बैंकस 10% और 11% ब्याज जमाओं पर चुकाएंगे दूसरी तरफ उन्हें आय के रूप में वृहत पूंजीनिवेश पर मात्र 5 से 8% ब्याज की प्राप्ति होगी। स्वाभाविक है अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे राष्ट्र के भी इस प्रकार की पूंजीनिवेश प्रणाली से घाटे में जाकर पहले जमाएं चाटेंगे, फिर पूंजीगत घाटे खाकर दिवालिया होने की कगार पर आ जाएंगे।

समय माया ने वर्षों पूर्व छापा था कि इन भू-माफियाओं की प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय व अन्य मंत्री कठपुतली बन नाचते रहते हैं। पहले उनके लिए कानूनों में परिवर्तन कर उन्हें कृषि भूमिस नजूल की भूमि चरनोई भूमि व अन्य इस तरह की अन्य कार्यों के लिए रखी गई भूमि उन्हें कालोनी काटने के लिए उपलब्ध करवाई गई। अब जब पूरे देश में इन जालसाज कालोनाइजरों न अरबों रुपए लगाकर चारों तरफ सभी बड़े शहरों में कालोनियां खड़ी कर दी है अब उनको बेचने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन को और रिजर्व बैंक के राज्य पाल को खरीदकर अपनी कालोनी के लिए जनता को ऋण पर कम ब्याज का लालच देकर फंसा रहे हैं। जब गृह ऋण ले लेंगे तो ब्याज दरों पर बेतहाशा वृद्धि कर दी जाएगी। उद्योगपतियों, भूमाफियाओं को यो जो छूंटे मंदी की आड़ में दी जा रही हैं पहले तो ये बताएं कि भारत में मंदी है कहां? क्या सस्ते में बिक रहा है गेहूं, शक्कर, तेल, चावल, सीमेंट क्या सस्ता हो गया।

मंदी के नाम पर चंदी बांट रहा है। हरामखोर अपने खास उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, कालोनाइजरों, भू-माफियाओं को खुले में जनता की छोटी-छोटी जमाओं को कम ऋण पर बांट कर जब ब्याज कम मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से बैंकों का अमेरिका की तरह दिवाला निकलने में समय नहीं लगेगा।

केंद्र की..

को कार ऋण, गृहऋण से ज्यादा जरूरी है। दो वक्त का भोजन, बच्चों की पढ़ाई जो दिनों दिन महंगी ही होती जा रही है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों की रिजर्व बैंक के माध्यम से केवळ सरकारी बैंकों तक पहुंचाया जा सकताहै, मानना न मानना उनकेही हाथ में होता है, फिर कुल जमा में ब्याज दरों की कमी का फायदा बड़े उद्योगों, कार निर्माताओं, सीमेंट कंपनियों, स्टील कंपनियोंकोही होगा जो कि कुल मिलाकर अगली लोकसभा के चुनाव की शिगूफे बाजी है। केंद्र सरकार की नियत का पता इससे ही चलता है कि वो पुनः देश के अच्छे गेहूं का तो निर्यात करेगी बदले में वर्षा के अभाव में गेहूं की पैदावार कम होने का बहाना लेकर पुनः सड़ा आस्ट्रेलियन गेहूं वहां से आयात करेगी, बची-खुची मंदी की कमी को वायदा व्यापार के सटोरिये चाट जाएंगे तो आम आदमी को क्या फायदा होगा। वर्तमान में शक्कर रुपए 20/- जो सितम्बर में रुपए 16-17 खाद्य तेल, सोयाबीन रुपए 55/-कि. मूंगफली रुपए 70/- गेहूं रुपए 10/- कि.का गेहूं 12 से 15/- तो आखिर क्या सस्ता हुआ है। कारें, गृह निर्माण, स्टील, पूंजीगत वस्तुओं का व्यापार आखिर कब तक तेजी पकड़ेगा? स्वाभाविक है बाजार की संतृप्तता पर बिक्री गिरेगी उसे मंदी के नाम से नवाजना मूर्खता होगी। मंदी से सचमुच उपभोक्ता वस्तुओं, दैनिक उपभोग

पेज 1 से जारी

की वस्तुएं तथा गेहूं, चावल, दाल तेल, दूध, सब्जियां, चाय, काफी, साबुन आदि सस्ते हों तो आंका जाना चाहिए कि वाकई मंदी है। इसके विपरीत पिछले तीन माह में ऐसे दैनिक उपयोगी वस्तुओं की कीमत गिरती तो ही आम आदमी को महंगाई से राहत मिलती और मंदी की सत्यता का आभास होता।

बेशक यदि भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड पेट्रो की दरों में आई 70% तक की गिरावट अर्थात 154 अमेरिकी डालर का सितम्बर-अक्टूबर की दरें वर्तमान में 40% अमे. डालर के हिसाब से 70% की अपेक्षा 50% की कीमतें कम कर दी होती, अर्थात रुपए 55/- का पेट्रोल रुपए 27- की कीमतों पर लौटता तो भी दैनिक उपभोग की वस्तुओं में भाड़े की लागत में 50% तक की कमी आ सकती थी, इसके विपरीत सरकार ने भात्र 10% ही कीमतें कम की इसकी तुलना में दैनिक उपयोगी वस्तुओं में मात्र 2 से 5% की जो कमी आनी थी वो बिचौलिये चाट ही गए, साथ विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने ऊपरी घाटे कम करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की एकत रफ तो कीमतें बढ़ाई, दूसरी तरफ अगर कीमतें नहीं भी बढ़ा सके, मात्रा कम कर दी गई। तो कैसी ओर कहां मंदी आई, या चुनाव की तैयारी के लिए वोट पाने का महज छलावा व षड्यंत्र है।

म.प्र. म.बा. विकास में करोड़ों का भ्रष्टाचार

करोड़ों खर्च के बाद भी कुपोषण से मौतें

इंदौर। जिले की महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती मंजुला तिवारी को सूचना के अधिकार में दिए गए पत्र से यहां से तो सूचनाएं नहीं मिली, तो जिलाधीश विवेक अग्रवाल को अपील दी गई, पर महिला अधिकारी से अपने संबंधों को निभाते हुए उन्होंने भी नकार दिया, अंत में म.प्र. राज्य सूचना आयोग से सौदा न पट पाने के कारण सारी सूचनाएं 18-11-08 को हमारे समय माया के कार्यालय में पहुंचाई गई।

कुछ दस्तावेजों के विश्लेषण से जो निष्कर्ष सामने आए तो चौंकाने वाले ही थे, जिन संस्थाओं को ये सहायता दी जा रही है उसके खर्च से तो कुपोषण तो छोड़िये बच्चों को मोटापे का शिकार होना चाहिए था। राशि महिला बाल विकास विभाग के विकासखंड व तहसील स्तर पर बनाए गए एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में बैठे परियोजना अधिकारियों को ही है। ये संस्थाएं जितनी मोटी रिश्वत दी जाती है उनती मोटी बिलों की राशि स्वीकृत की जाती है।

अधिकांश स्थानों पर आंगनवाड़ी केंद्रों में 50 से 80% तक पंजीयों में दर्ज बच्चे व महिलाएं फर्जी होते हैं, जो इन हरामखोर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला बाल विकास परियोजना केंद्रों के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीजुली भ्रष्ट कारगुजारियों से खुलकर डकारी जाती रहती है। जब 50 से 80% बच्चे और महिलाएं वास्तविकता में होती ही नहीं तो स्वाभाविक है 50 से 80% पैसा झूठे बिलों, व्हाउचरों के माध्यम से तो सीधा ही डकारा जाता है, फिर आपूर्ति किए गए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तो दूर कीड़ेदार दलिया व अन्य स्तरहीन सामग्री, दवाएं पौष्टिक आहार विटामिन्स आदि सबमें भी भारी कमीशनखोरी दलाली डकारी जाती है। कुछ संस्थाओं को उनके बिलों के द्वारा किए भुगतानों की बानगी पाठकों के लिए प्रस्तुत की जा रही है, यही रिपोर्ट फिर लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की जांच के लिए भी भेजी जाएगी, क्योंकि बिलों की छाया प्रतियां भी हमारे सूचना अधिकार के माध्यम से प्राप्त हो चुकी हो चुकी है। बेशक अधिकांश ऐसे स्वसहायता समूहों के पीछे कांग्रेसी व भाजपाई नेताओं के वरदहस्त के नीचे म.बा.वि. अधिकारियों के सहयोग से लाखों रुपए प्रतिवर्ष धन डकारा गया है। जिसकी सत्यता से पूर्व में भी हम बड़वानी जिले की ऐसे फर्जीवाड़े को प्रस्तुत कर चुके हैं। इंदौर म.बाल.विकास जि.अ.मं. तिवारी द्वारा बांटा गया कुछ संस्थाओं के नाम, उनके बिल व भुगतान की बानगी-

क्र.	विवरण	देयक/तिथि	राशि
1.	आदर्श स्व सहायता समूह गिरोड़ा तह देपालपुर	133554 22/9/05	255200
2.		149058 24/1/06	192303
3.		151184 23/2/06	207745
4.		62790 12/9/06	297000
5.		623125 16/10/06	146691
6.		137 25/01/07	166954
7		921042 20/3/07	163759
8		279 2007	392269.25
9		11 13/12/05	95975
कुल			1918496.25
1.	वैष्णवी स्वयं सहायता समूह इंदौर	बिल नं.02 15/7/05	180400
2.		141983 3/11/05	180400
3		215898 31/8/60	116192
4		216119 6/10/06	116600
5		223886 12/1/07	113114.25
6		224170 19/3/07	141337
7		223705 31/3/07	401502
8		आदेश 400/2सीडीएस/06 15/12/36	64075
9		बिल नं. 03 13/9/06	58300
कुल			1371920.25
1.	मां. एकवीरा महिला स्वसहायता समूह, इंदौर	138557 22/9/05	63800
2		215895 31/8/06	127600
3		223887 12/1/07	123785
4		224171 19/3/07	154689
5		223414 28/3/07	154671
6		देयक क्र. 05 19/10/05	63800
7		3/11/05 400ए/आईसीडीएस/06 15/12/06	77572.25
कुल			766017.25
1.	सरस्वती स्वयं सहायता समूह तहसील सांवेर	136708 26/8/05	103400
2		143122 22/11/05	106700
3		1274 9/6/06	611600
4		623194 16/11/06	379177
5		1964 26/2/07	660150
6		1758 14/12/06	16367.42
कुल		1884 29/1/07	1877394.42
1	श्रद्धा स्वसहायता समूह तह. सांवेर	136709 26/3/05	202400
1	शारदा स्वसहायता समूह ग्राम कनाड़िया	137101 30/8/05	123750
2		141980 3/11/05	134060
3		देयक क्र.012 15/2/06	256300
4		13 13/3/06	791176
5		449 13/6/06	432025
6		223368 29/1/06	124072
7		224173 19/3/07	186750
8		223410 28/3/07	505174
9		223409 28/3/07	158632
10.		223706 31/03/07	460355
		984 03/2/07	248145
	कुल		3320438.00
1.	इंदौर स्व सहायता समूह महासंघ ग्राम मोरोद	136711 26/8/05	266750
		546396 15/7/05	255410
		149056 24/1/06	127600
		04 09/3/06	133600
		141979 03/11/05	94600
			882960
1.	शक्ति स्वसहायता महासंघ	136712 26/8/06	616000
		150198 06/2/06	285120
		917101 31/3/06	630240
		30 27/01/07	316800
		132 19/2/07	744120
	कुल		2933320
1.	तुलसी स्वसहायता समूह	141981 03/11/05	369600
		135814 12/8/05	369600
		149035 24/1/06	558360
		05 10/11/05	310200
		151183 23/2/06	930600
		90 09/03/06	310200
		216295 29/11/06	381871
	कुल		2848598.1871
1.	जय मां संतोषी स्व सहायता समूह चम्बल तह. देपालपुर, जि. इंदौर	149059 24/02/06	209825
		151185 23/02/06	203660
		78 27/01/06	149600
		131 06/03/06	212300
		627902 12/09/06	281050
		03 10/01/06	94050
	आदेश क्र.	575 006	81835
	कुल		1232320
1.	समग्र क्रांति स्वसहायता (महिला) महासंघ, इंदौर	देयक क्र.107 15/02/06.	107800
		216120	107800
		06/10/06 223367 19/12/06	246142
		223994 29/01/07	248122
		223709 31/03/07	496245
		देयक क्र. 02 30/11/05	59400
1.	प्रगति स्व सहायता समूह जिला इंदौर	216273 16/11/06	147845
		223949 29/10/07	118999
		224174 19/03/07	149702
		223411 28/03/07	465973.375
		922602 03/04/07	320544
	कुल		1303063.375.
1.	प्रतिभा स्व सहायता समूह, सांवेर रोड इंदौर	223366 19/12/06	99249
		223710 31/03/07	198576
		आदेश क्र. 753 06/12/06	99249
	कुल		397074
1.	मां चामुण्डा स्वसहायता	1611 12/10/07	6546180
		1964 26/02/06	180042.45
		1752 14/12/06	65469.60
		1758 14/12/06	30885
		1611 12/10/06	65461.80
		1884 29/01/07	31950
	कुल		439270.65
1.	गुरु स्वसहायता समूह इंदौर	बिल नं. 03 25/08/05	48400
		141982 03/11/05	
1.	मधुमति स्वसहायता समूह इंदौर	223412 28/03/07	190601
		06 15/01/07	76053
		03/9/10/06 आदेश क्र.655 4/09/06	68687
		96-सी/19/1/07	95915
	कुल		431256
1.	श्रीबालाजी स्वसहायता समूह, सलमपुर. तह. देपालपुर	921045 20/03/07	164823
		आदेश क्र. 571/06	68197.37
	कुल		233020.37
1.	योजना स्वसहायता समूह, देपालपुर, इंदौर	721138 25/1/07	106761
		921044 20/3/07	108891
		922665 3/04/07	310931
		आदेश क्र. 571 29/8/06	68198
	कुल		594781
1.	म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्या. प्रेस यूनिट गोविंदपुरा भोपाल	1353 3/05/07	162240
2.	अजंता पैकिंग प्लांट	05 18/06/07	81000
	कुल		243240

मंत्री, इंजीनियर, पार्षद, ठेकेदार जनता को पानी पिलाने के नाम पर

पी जाते हैं अरबों का पानी

मोटी कमाई का साधन है, पानी पिलाना सभी संबंधित विभागों का

भोपाल। पूरे म.प्र. के उत्तरी चंबल संभाग को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर अल्पवृष्टि का प्रभाव तो पड़ा है। स्वाभाविक है जनता पीने के पानी के लिए भी तरस रही है। जनता पानी के लिए और उस आड़ में मंत्री लोक यांत्रिकीय विभाग के इंजीनियरों, नगर निगमों, पालिकाओं, परिषद्ों, महापौर, पार्षदों के पास दौलत बरस रही है।

जनता को पानी पिलाने के नाम पर शहरीय और ग्रामीण आबादी में हजारों नलकूप खोदे जाते हैं। जिसमें से 50% दिसम्बर, जनवरा आते-आते तक सूख जाते हैं। 25% नलकूप खनन के समय ही सूखे निकल जाते हैं।

हमारे प्रदेश में शहरीय व ग्रामीण आबादी को पीने व दैनिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध करने की जिम्मेदारी म.प्र. लोक स्वा. यांत्रिकीय विभाग की है। बड़े व जिला स्तरीय नगरों में नगर निगमों, पालिकाओं, परिषद्ों को जल वितरण का कार्य उनकी देखरेख में सौंपा अवश्य गया है, परंतु इंजीनियर्स लो.स्व. यांत्रिकीय विभाग के ही सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं और देखरेख करते हैं। यह भी कटु सत्य है, कि इस विभाग के इंजीनियर्स फिर भी तकनीकी दृष्टि से तरीके से कार्य करते हैं। इसके विपरीत छोटे-छोटे गांवों से लेकर महानगरीय जल वितरण व्यवस्था स्थानीय ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, परिषदों और निगमों के हाथ में होने के कारण वहां बैठे पंचों-सरपंच, पार्षदों से लेकर महापौरों तक यह पानी वितरण व्यवस्था पने स्वार्थपूर्ति और धन डकारने का एक बड़ा साधन है, यहां सारा खेल वोट बैंक के साथ कमाई दोनों तथ्यों के आधार पर ही जल वितरण और आपूर्ति होती जाती है। वह भी जहां पर धन मिलने की संभावना ज्यादा हो।

टैंकरों से पानी के वितरण के नाम हर पार्षद, महापौर से लेकर टैंकरों की स्वीकृति, डीजल की भरवाई, ड्राइवरों का वेतन, पानी भरवाने से लेकर पानी बांटने, बेचने तक हर कदम वसूली होती है। प्रति टैंकर अकेले इंदौर में एक पार्षद 15 से 30 हजार रुपए हर महीने कमाता है, उस पर विधायक प्रति टैंकर प्रति माह रुपए 3 हजार, महापौर रुपए 3 हजार प्रति माह, प्रति टैंकर पाईप लाईन से मिल जाता है। एक ड्राइवर यदि 8 टैंकर पानी की आपूर्ति करता है तो 4 वह बेचेगा व्यक्तिगत स्तर पर और 4 बांटेगा। यह हाल पूरे प्रदेश के 48 जिलों का ही है। अकेले टैंकरों से पानी पिलाने के नाम पर लगभग रुपए 800 करोड़ का खर्च नगर निगम, परिषद्, पालिकायें ही दिखा देती है। जिसमें अकेले इंदौर मेंही रुपए 55 करोड़ का चंदन लगाया जाएगा। जिसमें प्रदेश 14 नगर निगम ही रुपए 400 करोड़ का जनता को पानी पिलाने के नाम पर लगभग रुपए 200 करोड़ सीधे ही पी जाएंगे। इन नगर निगमों में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना आदि है। प्रदेश की 37 नगर पालिकाएं लगभग रुपए 200 करोड़ का, 237 नगर पंचायतों में लगभग रुपए 300 करोड़ का पानी जनता को पिलाने 50% तक पैसा डकार लिया जाएगा।

इन सबके लिए स्थायी जल स्त्रोतों के नाम और जल वितरण की आड़ में हर वर्ष अनियोजित बजट के नाम पर लगभग रुपए 500 करोड़ का बजट म.प्र. सरकार और नियोजित नए कार्यों के लिए रुपए 1000 करोड़ लगभग केंद्र सरकार देती है। जिसमें से यह विभाग ही रुपए 250 करोड़ का भ्रष्टाचार कर डकार जाता है, जिसमें घटिया स्तर की खरीदी से लेकर 10 से 25% खरीदी पर कमीशन निर्माण में कमीशन डकार लिया जाता है। इस संबंध में हाल ही में इंदौर लो. स्वा. यां. विभाग के मुख्य अभियंता भ्रष्ट डामोर के विरुद्ध और उसे सहयोग करते हुए संबंधित दस्तावेज न देने के आरोप में उसके अंधभक्त भ्रष्ट का.अ. पटवा, खरगोन, संभाग के विरुद्ध लोकायुक्त ने पाईप खरीदी घोटाले में विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। का.अ. पटवा का स्थानापन ले डूबा।

इंदौर मु.अ. डामोर जो पिछले दो वर्षों से सीधे ही कमीशन डकारने के लिए भ्रष्ट ल.उ.नि. को इंडेन्टजारी कर खरीदी करवा रहा है को सूचना क़े अधिकार में कितने इन्डेट जारी कर इंदौर, उज्जैन संभाग में खरीदी की गई कितना माल किस से उद्योग और आपूर्तिकर्ता ने कहां भेजा जानने के लिए दिया था तो बंदे ने उसे अपने अधीनस्थ अधीक्षण यंत्री इंदौर-उज्जैन के अंतरित कर जवाब देने से मुक्ति पा ली, जबकि इस मु.अभियंता के पास करोड़ों रुपए की अवैध सम्पत्ति झाबुआ में है। जमीन के किसी झगड़े में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उसमें इसके शामिल होने का एक मुकदमा भी इस पर झाबुआ के न्यायालय में लंबित है। हाल फिलहाल प्रमुख अभियंता का ख्वाब देख रहे मुख्य अभियंता डामोर पर लोकायुक्त का प्रकरण जांच में है, इसलिए प्रमुख अभियंता का सपना चूर हो गया।

झाबुआ में पेट्रोल पम्प, मार्केट आदि इस मुख्य अभियंता डामोर और उसकी पत्नी पूर्व कलेक्टर बुरहानपुर वर्तमान में अपर आयुक्त वाणिज्यकर कार्यालय में बैठी श्रीमती सूरज डामोर द्वारा कमाई गई भ्रष्टाचार की कमाई का ही है। आश्चर्य तो इस बात का है कि मु.अ. डामोर के विरुद्ध 1998 से हत्या का मुकदमा झाबुआ न्यायालय में लंबित होने के बाद भी यह इंजीनियर कार्यपालन से अधीक्षण और अभी मुख्य अभियंता बना बैठा है। न इसका निलंबन न सेवा से हटाया गया, आपराधिक प्रवृत्ति का यह अधिकारी इंदौर-उज्जैन संभाग के अपने अधीनस्थों के साथ कैसे पेश आ रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो उसके अधीनस्थ लगभग 20 का.अ. जिन पर ये ल.उ.नि से खरीदी के इंजेटर जारी कर कैसे माल की आपूर्ति की जा रही होगी, जनता को कैसे पानी पिलाने की कार्य योजनाएं पूरी हो रही हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

सच्चा पत्रकार होता है भावनात्मक संवेदनशील

इराक में बुश पर जूता-निपटे सस्ते में

५० लाख इराकियों की मौत, करोड़ों घायलों के बदले में नया जूता

अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने तेल के खेल के लिए रासायनिक और परमाणुवीय हथियारों की आड़ में आक्रमण कर पिछले 5 वर्ष में 50 लोगों की हत्या कर अकाल मौत दे दी और करोड़ों को घायल कर दिया। उसके बदले में करोड़ों में एक बहादुर निकला जिसने बिलकुल सटिक जवाब दिया। वह एक सच्चा राष्ट्रभक्त ईराकी था।

सच्चा पत्रकार ज्यादा संवेदनशील और भावनात्मक होता है जो गहराई से हर सच्चाई और वास्तविकता को समझता है। दुनिया की सच्चाई समझ में आरही थी पर ईराकी जनता को समझ में नहीं आरही थी। इसके विपरीत टी.वी. पत्करा मुंतजर अल जैदी ने अपने देश की बर्बादी तबाही, लाखों की अकाल मौत, करोड़ों घायलों को देखा, समझा और असहनीय मानसिक पीड़ा को बरसों भोगने के बाद उसने जो मौके का फायदा उठा कर जो किया बेशक वह भारी सराहनीय था।

उसने बुश की ईराक यात्रा के दौरान जो उसने प्रेस कांफ्रेंस ली, उसमें ईराक टीवी पत्रकार मुंतजर अल जैदी ने जवाब-सवाल के दौरान एक-एक कर दोनों जूते अमेरिकी राष्ट्रपति बुश को मारे, जिसमें बुश ने जूते आता देखव अपना सिर बचाया, इससे पूरे हाल में चंद सैकड़ों के सन्नाटा छा गया पर कुछ ही क्षणों बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को पूरी दुनिया ने टी.वी. पर देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बुश की ईराकी नागरिकों के प्रति किए गए अपराधों को करारा जवाब कैसे दिया गया।

रातों रात मुंतजर अल जैदी पूरे मुस्लिम जगत के साथ ही अमेरिका की आतंक फैलाने, दादागिरी हांकने की वास्तविकता को समझने वाला हर नागरिक बुद्धिजीवी का वह महानायक बन गया। उस जूते की एक अरब नागरिकों ने रुपए 1 करोड़ डालर जो भारतीय रुपए में करीब 48 करोड़ कीमत लगाई थी। वास्तविकता में उस जूते की नहीं वरन अमेरिकी जैसी विश्व की महाशक्ति के राष्ट्रपति बुश जो महालालची,हत्यारा, आतंकी, जिसने पूरे विश्व में आतंक फैला रखा हो उस पर फेंके जाने के सम्मान की कीमत है। उस ईराकी पत्रकार ने न केवल अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया वरन जिर अमेरिका ने अरबों डालर खर्च कर विमानों, टैंकों, नाटो सैनिकों का उपयोग कर ईराक पर आक्रमण कर नेस्तनाबूद किया बदले में उसके जवाब में एक सच्चा पत्रकार होने के नाते उसको सबसे सटीक जवाब देकर उस महाशक्ति को उसकी असली औकात दिखा दी। उससे पूरी दुनिया में हर सच्चे पत्रकार के दिल में उसके प्रति सम्मान ही होगा।

पानी की तलाश में ३६ करोड़ पानी में!

जहां पानी नहीं था, वहां लगाएं हैंडपम्प

भोपाल। जलसंकट से बचने के लिए सरकार ने पानी की तलाश में करोड़ों रुपए पानी में डूबो दिए। दरअसल अफसरों ने ऐसी जगह पानी की खोज शुरू की जहां भूजल रिपोर्ट्स पहले ही पानी नहीं होना बता चुकी थी। इस कारण बेकार पड़े हैंडपम्पों को पुनर्जीवित करने और नए हैंडपम्प खोदने में गलत जगह का चयन करने से करीब 36 करोड़ रुपए पानी में चले गए।

यह निष्कर्ष बढ़ते जल संकट से निपटने के दौरान सामने आयाहै। प्रदेश में बढ़ता जलसंकट सरकार के लिए चिंताखड़ी कर रही है। इस कारण हर स्तर पर जलसंकट से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सूत्र बताते हैं कि इस बेकार या बंद पड़े हैण्डपम्पों और अन्य जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने की मशक्कत शुरू की गई है। इसकेतहत जब पिछला रिकार्ड देखा गया तो सरकारी तंत्र ही फेल नजर आ रहा है। पिछले रिकार्ड के मुताबिक अभी तक सरकार ने ही जलस्त्रोतों को पुनर्जीवित करने को जो प्रयास किए, उनमें नीतिगत गलतियां हुई हैं। इन गलतियों के कारण करोड़ों रुपए डूबे हैं।

सूत्र बताते हैं कि जनवरी 2003 से दिसम्बर 2007 के दौरान निष्क्रिय हैंडपम्प और अन्य स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने में गलत चयन के कारण करीब 36 करोड़ 9 लाख रुपएका पानी बहा दिए गए। यह निष्कर्ष तब सामने आया जब सरकार ने बड़ी संख्या में जलस्त्रोतों के पुनर्जीवित होने के असफल प्रयासों की समीक्षा की। राज्य स्तर से जिलों को राशि जारी की, किंतु जिला स्तर पर जो जल स्त्रोत चयनित किए गए उनकी समीक्षा नहीं की गई। अधिकतर जलस्त्रोत ऐसे थे, जहां पानी की स्तरीय उपलब्धता को सर्वेक्षण नकार चुके थे। बावजूद सके उन जलस्त्रोतों पर फिर खुदाई व पुनस्थापना की गई, किंतु पानी नहीं निकला। इस बार इन स्थितियों को देखते हुए सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

बंद पड़े नलकूपों की स्थिति

2003-34,714
2004-32,993
2005-33,854
2006-37,738
2007-38,120

इस नलकूप खनन में लो.स्वा. यां. यांत्रिकी विभाग भी इस आड़ में रुपए 1 अरब से ज्यादा पूरे प्रदेश में डकार जाते हैं।

सौ दिन...

पेज 8 से जारी

कार्ययोजना के अंतर्गत जो धन स्वीकृत होता है, उसका उपयोग 31 मार्च के पूर्व ही पूरा करना होता है, इसलिए सारा काम कागजों पर ही तरीके से पूरा नहीं हो पाता। जमीनी वास्तविक सच्चाइयां पूरा होने का तो ख्वाब भी नहीं देखते और आसानीसे धन डकार लिया जाता है।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को ही लें,वर्षों से चल रहे ठेके तो अभी भी लंबित चल रहे हैं। नए रुपए 65% करोड़ भी डकारने में जाएंगे, रुपए 110 करोड़ ओंकारेश्वर नहर में क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि रुपए 178 करोड़ की टर्न की प्रोजेक्ट का दो वर्ष की समय सीमा नवम्बर 08 में समय पूरा होने के बाद भी 40% कार्य अधूरा है। फिर जाते-जाते रुपए 2800 करोड़ भी हाल ही में 4 माह स्वीकृत हुए थे। उनमें क्या हुआ? इसी प्रकार रुपए 300-400 करोड़ लोक निर्माण विभाग में स्वीकृत होंगे। पुराने कार्यों की समीक्षा और कार्य केवल कागजों पर ही पूरा हुआ होगा, जमीनी हकीकत बहुत अलग है। यही हाल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय का भी है। जो जनता को पानी पिलाने के नाम पर 100 दिन की कार्य योजनाका पानी रूपीधन डकार जाएंगे। जनता को पानी मिले न मिले।

इस श्रेणी जल संसाधन ग्रामीण यांत्रिकीय, स्वास्थ्य विभाग, कृषि उद्यानिकी, महिला बाल विकास, अंत्योदय, पंचायत व समाज सेवा, नगरीय प्रशासन जिला ग्रामीण विकास, जिला शहरीय विकास एजेंसियां, शिक्षा, आदि जाति कल्याण आदि ये सभी विभाग जो जन कल्याण से जुड़े सभी 100 दिन की कार्य के अंतर्गत अनुपूरक मांगों में बजट स्वीकार करवा कर पूरा कार्य कागजोंपर दिखा कर पूरा पैसा हजम, 1 अप्रैल से फिर 08-09 का बजट पर कार्य होगा। पीछे क्या हुआ, कितना काम हुआ, कितना धन खर्च हुआ, सब फाइलों में धूल खाता नजर आएगा। मुख्यमंत्री चौहान शायद नई पारी में डटकर भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचारियों को बचाओ, धन कमाओ की पारी खेलने की तैयारी में हैं। फिर लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। इसलिए सभी विभाग के अधिकारियों से लेकर सचिवों तक सब को चुनाव जीताने के तोहफे के रूप में धन डकारने का अवसर देकर शायद ये चार चली जा रही हो, कि जैसे आप लोगों को भ्रष्टाचार की छूट देकर आपने मुझे विधानसभा में बैठाया है, वैसे ही अब पुनः धन डकारने का अवसर 100 दिन के बहाने दिया जा रहा है। अब लोकसभा भी जिताने में मदद करें। इसलिए ही शिवा ने अपनी सरकार के गणों रूपी मंत्रियों और उनके मंत्रालयों में बैठे धूर्त राक्षसी आई.ए. सचिवों की इच्छानुकुल सूचना के अधिकार अधि. 05 का पूर्णतः गलाघोंट कर कोमा में पहुंचा दिया है। इस भोले-भाले चेहरे के पीछे का चेहरा, देखते रहिये आगे होता है क्या?

साप्ताहिक समय माया

जब तक जी ने चाहा दिल से खेला, जब चाहा छोड़ दिया

बिन शादी, कामचलाऊ दांपत्य- दोनों ही भयभीत

पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण, अगली पीढ़ी की बर्बादी

हमारे राष्ट्र में पाश्चात्य संस्कृति का जो अंधानुकरण हो रहा है, उसके दुष्यपरिणाम सामने आने लगे हैं। महानगरों से लेकर गांवों तक में परिवारों के विघटन और तलाक लेने की प्रवृत्ति भी उतनी तेजी से बढ़ रही है सबसे ज्यादा दुष्यप्रभाव बच्चों और आने वाली पीढ़ी पर पड़ रहा है।

महानगरों में तेजी से बढ़ती महात्वाकांक्षा, स्वच्छंद रहने और उन्मूक्त यौनाचार की प्रवृत्ति ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया है। जिसे 'लिव इ रिलेशन शिप' अर्थात् बिना शादी के स्त्री-पुरुष का दांपत्य जीवन जीना है। इस प्रकार के संबंधों को लेकर महिला बाल विकास केंद्रीय मंत्रालय और केंद्रीय महिला आयोग से लेकर केंद्रीय विधि मंत्रालय तक में गहन मंथन और विचार-विमर्श चल रहा है। बिना शादी स्त्री-पुरुष एक दूसरे के साथ दांपत्य जीवन जीते हैं। जब तक अच्छा लगता है साथ में रहते हैं, एक दूसरे को भोगते हैं, जब एक दूसरे से इच्छा भर जाती है या जब तक जी ने चाहा, दिल से खेला, जब दिल भर गया तो एक दूसरे को छोड़ दिया। इस तरह के 'लिव इन रिलेशन शिप' को लेकर उच्चतम न्यायालय ने ऐसे संबंधों से उत्पन्न संतानों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिएहैं कि ऐसी संतानें न केवल वैध मानी जाएंगी और यदि पुरुष बच्चे रखता है तो स्त्री को और स्त्री बच्चे रखती है तो पुरुष को स्त्रियों को खाना खर्च देना पड़ेगा। शादी होने या न होने से संतान की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

महाराष्ट्र सरकार ऐसे संबंधों को भी स्त्री-पुरुषों के संबंधों न केवल वैधानिक मान्यता देने की विधि मंत्रालय से गुहार लगा चुका है, इसके विपरीत महिला आयोग ऐसे संबंधों को शादी के बाद वैधानिक दांपत्य ही संबंध माना जाए। इस प्रकार के संबंधों को लेकर पूरे राष्ट्र का मीडिया भी गर्मागर्म बहस में उलझा है।

अब बिना शादी के संबंधों की जमीनी समीक्षा में जो सच्चाई सामने आई कि परिस्थिति जन्य ऐसे स्त्री-पुरुष निकट आए, परेशानियों और परिस्थितियों से समझौता कर साथ रहने लगे, दोनों की अति महत्वाकांक्षाओं ने शादी नहीं की परंतु दोनों ने शारीरिक संबंधों को अवश्य बनाया, ताकि तात्कालिक एक दूसरे से आवश्यकतापूर्ति की जा सके, बिना बाधा के उन्मुक्त जिंदगी जी सकें। साथ ही कोई भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन न करना पड़े, साथ ही पति-पत्नी रूपी संबंधों का भार भी न हो, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी न सामाजिक, न ही पारिवारिक किसी पर भी न हो, यहां तक की एक दूसरे की दिनचर्या, शारीरिक, मानसिक व अन्य प्रकार के संबंधों पर भी कोई अंगूली न उठाये, पूछताछ न हो, जिसको जो करना हो, दिनभर करे, रातभर करे, एक छत के नीचे, एक बिस्तर में सोकर सुबह अपने-अपने काम में लग जाते हैं। जिसको जो समझ में आए करे, जब तक दिल करे साथ में रहो जब दिल भर जाए तो अपने-अपने रास्ते अलग-अलग, तात्कालिक रूप से अल्पकाल में अच्छा लग सकता है, पर दीर्घकाल में दोनों एक दूसरे के प्रति भयभीत ही रहते हैं। कब कौन आ जाए, ये भय दोनों को ही रहता है, फिर वास्तविकता में

समय गुजरता जाता है। दोनों की जिंदगी का स्थायित्व भी नहीं मिल पाता है। साथ ही कोई भी नहीं चाहता कि शारीरिक संबंधों से बच्चे पैदा हों और जिंदगी एक दूसरे से बंधी रहे, यह व्यक्तिगत स्तर पर अच्छा लग सकता है, परंतु सामाजिक तौर पर ये समाज को बर्बाद हीकर रहे हैं। घाटे में स्त्री-पुरुष दोनों ही रहते हैं। साथ में समाज में परिवार के स्थायित्व के अभाव में समाज में भी विखंडन आएगा ही जो दीर्घकाल में दृष्टिगोचर होगा।

निःसंदेह यह भी सही है कि महानगरों में व्यक्तियों की जिंदगीयों में चार पल का सुकून भी काफी होता है। सारे दिन की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में सबकी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते किसी को भी किसी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। परिस्थितिजन्य संबंध स्थापित हो जाएं तो भी परिस्थितियां बदलते ही तार-तार बिखरने में वक्त नहीं लगता, जो समाज को और राष्ट्र को भी बिखेरेगा ही।

भाजपा की ऐतिहासिक जीत-जनता की मजबूरी

डकैतों के दल-दल में भ्रष्टों को चुनना

पुराने वादे पूरे नहीं, नए वादों के हश्र भी देखेंगे

भोपाल। 13वीं विधानसभा में जनता ने फिर से भाजपा को गद्दी मजबूरी में सौंप दी है, बेशक भाजपा ने प्रदेश के इतिहास में उलटफेर कर कांग्रेस के इस भ्रम को तोड़ दियाहै कि कोई भी दल उनके अतिरिक्त सरकार नहीं चला सकता। इन अर्थों में भाजपा ने भले ही पिछली सरकार में तीन मुख्यमंत्री भले ही देखें हो परंतु 5वर्ष सत्ता चला कर पुनः सत्ता में जनता ने विश्वास व्यक्त किया।

पूरे प्रदेश की सत्ता ने कांग्रेस के 40वर्षों के शासनकाल को देखा है उसकी तुलना में भाजपा ने कुछ बेहतर किया, दूसरा प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के अतिरिक्त किसी तीसरे दल का इतना मजबूत अस्तित्व ही नहीं था,यही जनता की मजबूरी थी, कांग्रेस के त्राहि-त्राहि शासन से उन्होंने भाजपा को और मुख्य रूप से मुख्यमंत्री की भोली शक्ल को जनता के प्रति समर्पण की गंभीरता को देखकर ही पुनः बहुमत से जिता दिया।

कांग्रेस उन मोटे डकैतों की पार्टी बन चुकी है, जिसे जनता के धन पर डाका डाल डकार जाने से ही मतलब रहा है। इसके विपरीत भाजपा के भी अधिकांश विधायक न केवल भ्रष्ट अपराधी, जालसाज है, वरन इन्होंने भी प्रदेश को कई स्तरों पर चौपट किया, जिसमें मुख्यरूप से भू-माफियाओं, अवैध कालोनाइजरों को न केवल खुलकर सहयोग किया, वरन् नजूल की जमीनों, कृषि भूमि, चरनोई की भूमि पर इन्होंने खूब भू-उपयोग परिवर्तन करवा कर स्वयं भी करोड़ों अरबों रुपए की कमाई की ओर उससे सैकड़ों गुना लाभ पूंजीपतियों, अवैध कालोनाइजरों, भू-माफियाओं को जनता को लुटवा कर लाभ पहुंचाया, जिसकी चर्चा पूरे मीडिया में छाई रही, पर बेशर्मो का लूटपाट में शर्म नहीं आई।

वर्ष 2007-08 में तो न केवल हर विभाग का मंत्री, विधायक वरन मुख्यमंत्री शिवराज भी इन धूर्त डकैत, भ्रष्ट, जालसाज भूमाफियाओं, कालोनाइजरों की कठपुतली बन नाचता, नियमों, कानूनों को बलाए ताक रखकर प्रदेश की जमीनों को अपनी बपौती समझकर दोनों हाथों से धन बटोरा गया। जनहित के भूत, वर्तमान, भविष्य इनके लिए औचित्यहीन हो गए, ये मुखैरों की भांति जमीनों की वैध-अवैध तरीकों से खरीद, फरोख्त कर आंख मींच नोंच खसोट करते रहे।

दूसरा अपने जीवन पर्यंत स्थाई लाभ प्राप्त करने के लिए लो.नि.वि. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, म.प्र. सड़क विकास निगम का महाजालसाज, मक्कार, सुलेमान, प्र.सं. अधिकांश उच्च यातायात वाले राज्यमार्गों को कई गुना ज्यादा कीमतों पर सड़कों की नीलामी बीओटी के अंतर्गत कररहा है, वर्तमान में दो हजार कि.मी. से ज्यादा की सड़कें न केवल नीलाम रक जनता के वाहन चालकों से अनाप-शनाप वसूली में जुटी हैं। इस संबंध में वीवा हाइवेज की मुख्यकंपनी अशोक बिल्डकॉन के इंदौर, खंडवा, ईच्छापुर मार्ग को ही देखें तो ये 27' चौड़े मार्ग पर वसूली शुरू हुए 5वर्ष गुजरने के बाद भी न तो सील कोट किया गया और न ही दोनों ओर की 5'-5' की पट्टियां भरी गईं।

तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा बिजली का है, जब से विद्युत मंडल को कंपनियों में बांटने का सिलसिला चालू हुआ है केवल लूट-खसोट बढ़ी हैं। उन हरामखोर इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों को विद्युत इंजीनियरिंग का क,ख,ग, नहीं आता है। इसके बावजूद इन धूर्तों को उन कंपनियों में प्रबंध संचालक बनाकर बैठा दिया जाता है। उन गिद्धों को केवल नोंच खसोंट आती है। कानून उनके बाप की जागीर होती है जिसे वो जेब में लेकर चलते हैं। ये वो उल्लू होते हैं जिस शाख पर बैठते हैं उस गुलिस्तां को उजाड़ कर वीरान कर देते हैं। चाहे तो विद्युत वितरण कंपनियां हो, एकेवीएन हो या पूरा प्रदेश हो।

इनके बैठने के बाद विद्युत मंडल की चहुं और सिवाय बर्बादी के मंजर के अतिरिक्त कुछ नहींरह गया है। अधिकांश कार्य ठेकों पर जो मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों के भाई-भतीजों को सौंप दिए गए हैं कदम-कदम पर लूट का तांडव मचा हुआ है। क तरफ बेतहाशा बिजली की कीमतें बढ़ाई जारही हैं, दूसरी तरफ किसी को भी 24घंटे निर्बाध आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। चारों तरफ सफेदपोश डकैतों का तो साम्राज्य है ही, तीसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण ग्रामों के विद्युतीकरण की बात तो दूर गांवों में तो 12 से 22 घंटों की कटौती वर्षों से चल ही रही है। गांवों के 90% ट्रांसफार्मर्स या तो खराब पड़े हैं या गांव वालों से चंदा करके एकत्र किए रुपए 25 से 50 हजार में विद्युत वितरण कंपनियों के इंजीनियरों ने वसूली कर लगाए हैं। रखरखाव के नाम का ट्रांसफार्मर्स के तेल से लेकर खम्भों तक की पुताई का पैसा तक आई.ए.एस. से लेकर सुपरवाइजर तक सब डकारने में लगे हैं। यह हाल पूरे प्रदेश का है। जिसमें भाजपा सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों ने भी बर्बाद होते मंडल को निचोड़ा ही है।

वैसे भी अतिशीघ्र कांग्रेस की तरह यह सरकार भी कुछ जनोपयोगी विभागों को बंद करने की तैयारी में खड़ी है जैसे कि म.प्र. का लोक निर्माण विभाग का राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, उसके पास जितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे इन में से अधिकांश पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कब्जा कर के.बी.ओटी से टोल वसूलेगा, बचे हुए मार्गों को म.प्र. शासन का म.प्र. सड़क विकास निगम छीनकर उलटे सीधे 4 लेन सड़कों पर ही लीपापोती करवाकर ठेकेदारों से टोल वसूल कर वाहन चालकों से लूटमार मचाएंगे।

भाजपा की नई सरकार का, अधिकारियों को पुरस्कार

सौ दिन की कार्ययोजना पूरी होगी कागजों पर

भोपाल। म.प्र. में भाजपा सत्ता में पुनः जीत कर पहुंच गई, इसमें शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने अप्रत्यक्ष रूप में गहन भूमिका अदा की जिसे स्वयं मु.मं. शिव ने स्वीकारा। शिवराज म.प्र. की जनता की प्रति समर्पित हैं। 60% उनकी नियत पर शक भी अभी तक बेमानी नजर आया। 40% उनकी नियत भले ही साफ हो, परंतु भ्रष्ट इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के महाधूर्तों, हरामखोरों, महाभ्रष्टों की कारगुजारियों से उछलने वाले कीचड़ से दाग तो शिव के दामन पर ही लगाए जाएंगे। इसका सीधा और सटीक उदाहरण है सूचना के अधिकार अधिनियम में किए गए आदेशों से उस अधिनियम की मूल भावना पारदर्शिता का न केवल पूर्णतः गला घोंट दिया गया, साथ ही अगर शिव में थोड़ी सी शर्म और ईमानदारी बची होती तो न केवल उन आदेशों को भी नहीं निकलता और न ही ऐसी धूर्तापूर्ण चालों का गजट नोटी फिकेशन करवाता, इसलिए वास्तविकता में तो सत्ता की भ्रष्टाचार और धूर्तापूर्ण चालों का गजट नोटीफिकेशन करवाता, इसलिए वास्तविकता में तो सत्ता की भ्रष्टाचार और धूर्तता की कालिख में इस महत्वपूर्ण तथ्य ने सिद्ध कर दिया है कि लंबी शांति से छलांगे लगाई जा रही है। भले ही आवाज न हो रही हो, पर अपने कुकर्मों और भ्रष्टाचारों की सच्चाई जनता के हाथ न लगे इसलिए सूचना के अधिकार अधि. 05 में हर नागरिक को सूचना पाने का अधिकार है, में यह व्यवस्था कर दी गई है कि बिना राज्य सरकार की आज्ञा के बिना जानकारी न दी जाए जैसे पूरी सत्ता इनकी बपौती है। कानून अपनी रखैल। जैसे चाहो उपयोग करो, वास्तविकता में तो कुछ मामलों में ये दिग्गी दानव से ज्यादा तांडव कर चुके हैं। इनके गणों ने भी भरपूर तांडव किए हैं। जंगल काटने साफ करने से लेकर मरीजों की दवाइयां डकारने तक बिल्डरों को जमीनें बांटने, बेचने से लेकर महत्वपूर्ण सड़कों तक को जो केंद्र सरकार के राजमार्ग थे उन्हें भी छीनकर इन हरामखोरों ने उन सड़कों को ठेकेदारों को बेच कर मोटी कमाई की और बनाने, निर्माण करने के नाम पर वाहन चालकों से लूटने के लिए सड़कों पर कानूनी डकैत बैठा दिए। केंद्र सरकार ने गैस, पेट्रोल, डीजल पर दाम घटाए भी तो तत्काल इन्होंने उस पर टेक्स थोंप दिए।

अब मु.मं. शिवराज ने 100 दिन की कार्य योजना बना कर जनहित के कार्यों को सम्पन्न करने की जो घोषणा की है हो सकता है कि इनकी नियत साफ हो, पर घोषणा करते ही म.प्र. लोक निर्माण, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकीय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, कृषि उद्यानिकी, वन विभाग, पुलिस जैसे अधिकांश विभागों के जिला अधिकारियों से लेकर विकास खंड अधिकारियों से लेकर विकासखंड अधिकारियों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के मुंह में पानी भर आया है। दिसम्बर, जनवरी में जो पूरक बजट पास होता है, उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अभी अनुपूरक बजट पास होना है, अनुपूरक बजट में 100दिन की शेष पेज 3 पर

प्रतिबंधात्मक सूचना

इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उसके आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एपिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र या राष्ट्र के बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डाक्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें. अन्यथा कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस समाचार पत्र की प्रतियां लेकर कुछ जालसाज ढोंगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं.

आज्ञा से
प्रधान संपादक

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु. 299-अंबेडकर नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इन्दौर द्वारा मुद्रित. बडवानी प्रतिनिधि-नरेश नायक मो. 94250-90602, भुपेन्द्र बिल्लोरे मो.99934-49774
कम्प्यूटराईजेशन- सुनील जोशी 93290-40982, भोपाल प्रतिनिधि एस.के. भारद्वाज मो.94256-37958, खंडवा प्रतिनिधि सुशील परिहार मो. 97554-76530, इन्दौर कार्या. फोन 2304377 मो. 93007-55803